जनपथ

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी(माओवादी)
महाराष्ट्र-मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ स्पेशल जोनल कमेटी का मुखपत्र

अंक पहला जुलाई 2019

मोदी की जीत जनता की जीत नही ब्राम्हणवाद की जीत है।

17 वी लोकसभा के चुनाव मई 2019 मे संपन्न हुए है। इसमे 543 सिटों मे से भारतीय जनता पार्टी को 303 मिले है। और बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए(नॅशनल डेमोक्राटीक अलायन्स या राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन) को 353 सिटें मिली है। काँग्रेस को केवल 52 सिटें मिली है। उत्तरप्रदेश जहाँ बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल मिलकर महागठबंधन बनाया था उनको केवल 15 सिटें मिली है, जबकि भाजपा को 62 सिटें मिली है। बीहार मे राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व वाले गठबंधन का सफाया हुआ है। बीहार मे बीजेपी, युनाईटेड जनता दल और रामविलास पासवान की लोकजनशक्ति मिलकर गठबंधन था उनको लगभग शतप्रतिशत सफलता मिली। नरेन्द्र मोदी फिर वापस दुसरे पाँच साल के कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री बने है। अपने परम मित्र अमित शहा को गृह मंत्री बनाया है। मोदी इस जित को लोकतंत्र की जीत कहते है, नये भारत के कार्यक्रम को दिया जनादेश कहते है, उनके सरकार के कामकाज को दिया जनादेश मानते है। क्या वाकेही यह मोदी सरकार के कार्य को दिया जनादेश(पेज नंबर 4 पर)

संपादकीय

मोदी जीता भारत हारा

लोकसभा चुनाव नरेन्द्र मोदी ने जीत लिया पर 'भारत' हार गया। भारत ने इस लोकसभा चुनाव से कई उम्मीदे बांधकर रखी थी पर वह सब धाराशाही हो गए। भारत रोजगार चाहता था, भारत किसानों की फाँसी के फंदे से मुक्ति चाहता था, भारत को उम्मीद थी कि नोटबंदी और जीएसटी का मार झेले लोगों के जख्मों पर मरहम लगेगा, भारत ने सोचा था अब कम से कम बीफ खाने पर की पाबंदी हट जायेगी और गरिबों के खानपान मे आसानी से प्रोटीन की पुर्ती हो पायेगी। भारत चाहता था कि विचारों की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बेड़ीयाँ टुट जाय, एनपीए के माध्यम से किए जा रहे भारी घोटालों का पर्दाफाश हो और पूंजीपति, नेता और बैंक अफसरों ने मिलकर गबन किए रकम की वसुली कर जनता के हित मे खर्च हो। भारत उन चंद घरानों के कब्जे मे केन्द्रीत संपत्ती पर देश का हक चाहता है, भारत की समज है कि वह संपत्ती भारत की मेहनतकश जनता के हाडतोड मेहनत का मुल्य है, वह देश के विकास मे खर्च होना चाहिए। भारत उम्मीद बाँधे बैठा है कि फिसल गई अर्थव्यवस्था की गाडी पटरी पर आ जाय। झुठ, पाखंड, जुमलेबाजी से उब चुका भारत राहत की सांस लेना चाहता था। खुद ही खुद की डिंगे हांकते

(पेज नंबर 15 पर)

इस अंक मे : –

1. मोदी की जीत जनता की जीत नही है –– 1
2. मोदी जीता भारत हारा––2
3. भारत मे दो राजनीति ––3
4. सबका साथ सबका विकास ––18
5. तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था ––22
6. आमदानी दुगनी ––29
7. बलिदान की गाथा ––37
8. शहीद सप्ताह मनाओ ––44

राजनीतिक तरंग

भारत मे दो राजनीति, तुम किस तरफ?

वैसे तो चुनाव मे जो खडे रहते है वह आम जनता के सच्चे प्रतिनिधी नही होते। आज तक का जनता का अनुभव है कि जो भी जीतकर आता, है अंत मे बड़े पूंजीपति और जमीनदार वर्ग के हित मे ही काम करते है, साम्राज्यवादीयों की सेवा करते है। चुनाव मे एक तरफ नागनाथ तो दुसरी तरफ सांपनाथ होते है। कोई भी चुनकर आए आम जनता के लिए तो जहर ही उगलने वाले है। भारत की जनता, यह एक बार, दो बार नही अब तक 16 बार देख चुकी है और अब 17 वी बार देखने जा रही है।

सम्राज्यवादीयों के दलाल, भारत के शाशक वर्ग ने अपने चरित्र के अनुसार दलाली करने मे महारत हासिल करने वाली भ्रष्ट लोंगों की एक चापलुस तादाद पैदा की है। यह समाज के हर तबके मे पैदा किया है। यह देश की 130 करोड जनसंख्या की तुलना मे अत्यंत छोटा तबका है पर यह समाज मे असरदार भूमिका निभाता है। क्योंकि इसको सत्ता का सपोर्ट रहता है। यह भारत के दलाल पूँजीवाद की व्यवस्था का एक कलपुर्जा है। यह इस दलाली करने की और भ्रष्टाचार करने की आजादी को जनता की आजादी के रुप मे पेश करते रहता है, इसके प्रभाव मे आम जनता इसे आजादी ही समज बैठे है। इस आजादी ने चुनाव का एक चक्रव्युह बुना है जिसमे जनता फँसी है। अगर यह आजादी है तो फिर सबको रोजी, रोटी, स्वतंत्रता, समता, न्याय और भाईचारा प्राप्त हो ऐसे व्यवस्था को क्या कहेंगे? अगर आज आम जनता को यह सब नही है तो यह कैसी आजादी है? यहाँ तक सवाल तो सभी करते है पर सवाल है इस स्थिती को बदलने का। इस चक्रव्युह को तोडने कई अभिमन्यू विरगति को प्राप्त हुए है और सतत हो रहे है। सिलसिला अब भी जारी है, एक तरफ सम्राज्यवाद के सेवक दलाल नौकरशहा पूँजीपति और जमीनदार वर्ग है तो दुसरी तरफ आजादी की चाहत रखने वाली जनता है।

सच्चे आजादी के लड़ने वालों की राजनीति एक किस्म की राजनीति है तो विकास के नामपर (पेज नंबर 10 पर)

(मोदी की जीत.. पेज नंबर 1 से) है? क्या इसे इमानदारी से जनता की वास्तविक ईच्छा मानना चाहिए? क्या यह चुनाव पध्दती देश की जनता की ईच्छा और आकांक्षा का प्रतिबिंब होता है? मोदी के इस भारी बहुमत का किसीको क्यों अंदाज नही लगा? इतने बडे देश का इतना व्यापक नेटवर्क वाला मिडीया जो लगभग 99 प्रतिशत मोदी के भक्त है उनको भी मोदी के करामात की भनक ना लगे यह कैसे हो सकता है? लगभग सभी मिडीया उनका अंदाज गलत हो गया, आंकलन करने मे फेल हो गए कह रहे है। और अब चुनाव नतीजे आनेपर चर्चा कर रहे है कि मोदी की लहर थी, मोदी के कार्य से जनता खुश थी। क्या वास्तविक रुप से जनता खुश थी? नोटबंदी, जीएसटी, अर्थव्यवस्था की बर्बादी, रोजगार घटना, किसानों के आत्महत्याएँ और दलित और अल्पसंख्यांकों पर हमले और सामाजिक दहशत। यह सब विपरित मुद्दे रहने के बावजुद मोदी को वोट क्यों मिले? मोदी ने क्या किया और क्या नही किया, जनता को क्या मिला और क्या नही मिला? आर्थिक या भौतिक रुप से जनता को क्या मिला? क्या केवल भौतिक रुप से प्राप्त चिजों के व्दारा जनता के मत बनाये जा सकते है? यह कहा जा रहा है कि यह मोदी और अमित शहा की जबरदस्त सोशल इंजिनियरिंग है। (सोशल इंजिनियरींग का मतलब है चुनाव मे असरदार वोट प्रतिशत वाली जातियों के नेताओं को खरिदना और जाति के हिसाब से धृविकरण दृढकर उन्हे अपने साथ जोडना) भारत का चुनाव और चुनाव पध्दती को जो लोग सत्ता परिवर्तन का माध्यम मानते है उनके लिए यह अनपेक्षित है। और जो इसे सत्ता परिवर्तन का माध्यम नही मानते बल्कि सरकार चलाने वाले व्यक्तियों का बदल मानते उनके लिए यह कोई आश्चर्य नही है। हां यह जरुर देखने की बात है कि जनता के विकास के वास्तविक कारक विपरित रहने के बावजूद भावनात्मक और जुमलेबाजी के बलपर भारी बहुमत कैसे प्राप्त किया?

मोदी ने चुनाव मे कौनसे मुद्दे सामने लाए? विरोधियों ने कौनसे मुद्दे सामने लाए? इससे भी हम यह देख सकते है। राहुल गांधी के भाषण मे गलती से भी एक बार भी भारत का उल्लेख नही है, वह मोदी से भी ज्यादा हिन्दूस्थान, हिन्दूस्थान चिल्हाते रहा हिन्दू वोट बैंक को अपने तरफ खिंचने की

यह कोशिश थी। मोदी को 'बॅड मॅन' बनाने की बचकाना कोशिश केवल राफेल के एक ही मुद्दे पर की गई जो बीजेपी के आक्रमक प्रचार के सामने टीक नही पाया। हमे कोई आवश्यकता नही कि काँग्रेस के हारने के कारणों को या मोदी के जीतने के दाँवपेंच को लेकर कोई आंकलन पेश करना। पर हमें यह जानना जरुरी हो जाता है कि किस तरह सत्ताधारी वर्ग उसके जरुरतों के लिए ब्राम्हणी हिन्दू फासीवादी सरकार लाना चाहते है तो कैसे भी वे ला सकते है। हमे इस चुनाव के व्दारा यह समज दृढ बनाने के लिए चर्चा करना जरुरी है कि चुनाव के व्दारा सत्ता बदल नही होता, सत्ता उसी वर्ग की रहती है, मात्र उसे चलाने वाले सरकारी प्रतिनिधी बदलते है। हमे इस बात की तोड निकालने के लिए यह जानना जरुरी हो जाता है कि किस तरह फासीवादी ताकतें जनता के ज्वलंत विषयों (वास्तविक विकास के विषय) को हाशिए पर डालकर गलत राजनीतिक चेतना मे मोड देते है। यह बहुत ही महत्वपुर्ण है कि जनता को सही राजनीतिक चेतना के तरफ मोड देना।

मोदी जानते थे कि उनके टक्कर मे केवल काँग्रेस के पास देशव्यापी संगठन है इसलिए पूरे पाँच साल जब भी जहाँ भी मौका मिला वह काँग्रेस को राजनीतिक विलन और खुदको हिरो के रुप मे पेश करते रहे। अगर मोदी को अच्छा दिखाना है तो किसीको तो बुरा दिखाना जरुरी है, इसिलिए मोदी ने अपना दुश्मन काँग्रेस को चुनकर भाजपा के कुनबे को लड़ाई कर जितने का मिशन दे दिया। काँग्रेस के पास इसके खिलाफ आक्रमक जवाब देने के कई आधार है फिर भी राहुल गांधी का विरोध हमेशा नौटंकिया अंदाज मे रहता था। काँग्रेस विरोधियों के सारें मंचो पर जाती रही पर मोदी के खिलाफ देशव्यापी मोर्चा बनाने पहल नही की, या युं कहे तो बनने नही दिया। यह सत्ताधारी वर्ग की सोच समजकर 17 वी लोकसभा के लिए बनाई गई योजना का एक हिस्सा है, इस तरह इसे देखने से सही राजनीतिक दृष्टी आंकलन करने के लिए मिलेगी।

जब मोदी जरुरी है, तो चाहे कोई भी मुद्दे सामने लाए अंत मे उसका नतिजा यह होना चाहिए कि हिन्दू मतों का धृविकरण होना चाहिए यह मोदी के वोट बैंक की राजनीति की मुख्य थिम है। इसके अलावा मैदान मे जो है

उनसे वह अच्छा है ऐसी सोच बनाने के कारक प्रचार मे ज्यादा होना चाहिए यह दुसरी उप थिम है। सर्व समावेशी होने का दिखावा, नये वोटरों की सोच को व्यवहारीकता के पैमाने पर लेकर आने की भरकस कोशिश आदी रणनीतिक थिम पर चुनाव का व्यवस्थापन किया गया।

मुख्य राजनीतिक थीम (हिंदू वोट धृविकरण) की सफलता के लिए देश की सुरक्षा और देश का विकास और उसके लिए मजबूत सरकार वह केवल मोदी दे सकता है ऐसे मोदी ब्रँड की टीआरपी हायपीच पर ले जाना जरुरी था। वह पुलवामा बालाकोट जैसे घटनाओं से ही किया जा सकता था। सतत पाँच साल इस ब्रँड को भाजपा से भी बढ़कर बनाकर रखा गया था, चुनाव के समय पर सवाल सिर्फ उसे उच्चांक पर ले जाना था। वह देशभक्ती और मजबूत नेतृत्व का एहसास के लिए पुलवामा करते हुए बालाकोट किया गया। काश्मिर और भारत पाकीस्थान की बॉर्डर जहाँ सेना का कन्ट्रोल रहता है, वहाँ का सच और झुठ कोई नही जान सकता। सरकार जो बतायेंगे उसपर ही सबको निर्भर होकर रहना पड़ता है। सच को केवल परिस्थिती के संदर्भ के साथ जोडकर ही समझा जा सकता है। मसलन चुनाव के मोहरे पर पुलवामा और बालाकोट होना मोदी की जरुरत थी। इससे मोदी को सशक्त देशभक्त, मजबूत नेता, पाकिस्थान को सबक सिखाने वाला ऐसे हीरो के रुप मे खड़ा होने मे मौका मिला। सारी नाकामीयों को धुँधलाकर देश और देश की रक्षा और उसके लिए मोदी यह माहौल बनाया जा सका इसका मोदी को राजनीतिक फायदा हुआ। तब संदेह होता है कि, पुलवामा और बालाकोट किसी आतंकवादी गुट ने किया हमला नही बल्कि भारतीय सत्ताधारी वर्ग के पास जो आतंकी एजेन्सीयाँ है उसकी यह करामात ज्यादा लगती है। इस तरह राजनीतिक चर्चा के पटल पर आर्थिक और सामाजिक मुद्दों के बजाय देश की सुरक्षा का मुद्दा लाकर खड़ा किया। जनता को न्याय और अन्याय के बजाय देश के बारे मे सोचने को लगाया। इसको पाकिस्थान विरोधी और मुस्लिम विरोधी के रुप मे भुनाकर हिन्दू वोट का धृविकरण करने इस्तेमाल किया। देश और देशभक्ति के (राष्ट्रवाद) दो विचार भारत मे पनपते है। दोनो ही हिंदू राष्ट्रवाद (प्रतिगामी) ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि भाजपा इसे कट्टर

हिन्दूत्व के रुप मे सामने लाता है तो काँग्रेस नरम हिन्दूत्व के रुप मे। अन्य बाकी क्षेत्रिय, समाजवादी से लेकर चुनावी कम्युनिस्टों तक जो राजनीतिक पार्टीयाँ है वह इन्ही दोनो के इर्द गिर्द है। राष्ट्रवाद के मामले मे कोई भी पुरोगामी नही है। भाजपा का राष्ट्रवाद मुस्लिम और पाकिस्थान विरोध से ही जगह पाता है। वे उनके राष्ट्रवाद को दुश्मन के बिना स्थापित नही कर सकते, यह सावरकर से लेकर आरएसएस और भाजपा तक के लंबे सफर की रणनीति रही है।

सच्चे जनवादीयोंको, अमन पसंद जनता को, क्रांतिकारीयों को इस चुनाव के नतिजे मे कोई हैरानी या विचलन नही होना चाहिए। क्योंकि एक तो मौजुदा चुनाव पध्दती से राज्यसत्ता मे कोई बदलाव नही आता है। दुसरा यह चुनाव पध्दती सत्ताधारी वर्ग के बीच सरकार बनाने के लिए निर्णय करने का माध्यम है। तीसरा जनता इसमे मात्र माध्यम है, उनका इसके व्दारा सत्ता मे कोई अधिकार, हक या हिस्सेदारी नही होती है। मोदी जीते या काँग्रेस हारे इस बात को लेकर शोषित जनता को, जनता के पक्षधर जनवादीयों और बुध्दिजिवीयों को भी कोई खुषि या गम की बात नही होना चाहिए। काँग्रेस क्यों हारी इसका सिंपल उत्तर यह है कि मोदीको जिताना था। काँग्रेस मात्र एक पार्टी नही है वह परखी हुई साम्राज्यवादीयों की साम्राज्यवादीयों ने ही बनाई हुई भारत के लिए राजनीतिक व्यवस्था है। वह भारत के सभी धाराओं को शामिल करते हुए साम्राज्यवादीयों के सेवामे धृविकृत करती है। इसमें आरएसएस को मानने वालों से लेकर आंबेडकरवादीयों तक, मुस्लीम, और अन्य पंथ वाले, उदारमतवादी और यहाँ तक कि चुनावी कम्युनिस्टों को भी पिछलग्गु बनाकर रखने की क्षमता है। भाजपा कितनी भी एकतरफ कट्टर हिन्दूत्व का बोलबाला करने पर भी उसे भारत जैसे देश मे राज करना है तो पार्टी को काँग्रेस जैसी व्यापक छत्री बनाना पड़ेगा। इसलिए डायरेक्ट कई काँग्रेस नेताओं को ही शामिल कर लिया और ऐसे नेताओं और पार्टीयों को भी साथ मे रखा है जिससे यह दिखे की वह सर्व समावेशी है।

जो भी हो चुनावी पार्टीयों के लिए मोदी–शहा की चुनावी रणनीति एक आव्हान बन गया है। हिन्दी बेल्ट के हिन्दूओं को केवल हिन्दूत्व के नामपर

प्रभावित नही किया जा सकता इसलिए देश की सुरक्षा को साथ मे जोडकर प्रभावित किया। यह बेल्ट मुख्य रुप से भाजपा का आधार है। बंगाल मे ममता के फासिवादी राज के खिलाफ सक्षम विरोध का अभाव है, उस खालिपन को पाटने भाजपा को मौका मिला। कर्नाटका मे कॉंग्रेस–जेडिएस अन्य स्थानिय क्षत्रपों को सम्मीलित करने मे (सत्ता बॉंटने मे) कामयाब नही हुए। ओडिशा मे नविन पटनायक से बेहत्तर दलाल साम्राज्यवादीयों के लिए दुसरा नही है इसलिए वह उसे नही बदलेंगे। आंध्रा मे चंद्राबाबू और जगन मोहन दोनो एक ही थाली के चट्टेबट्टे है इसलिए सत्ताधारी वर्ग को कोई फर्क नही पड़ता की कौन रहना, यह स्थानिक राजनीतिक माहौल पर निर्भर होकर वह चलाते है। तेलंगना मे चंद्रशेखर राव जनता को गुमराह करके साम्राज्यवादीयों को अच्छी सेवा दे रहे है, पिछले पाँच साल टेस्ट भी हो चुका है फिर उसे क्यों बदलेंगे? तामिलनाडु घुम फिरकर द्रविड अस्मिता के बाहर किसीको बर्दाश्त नही करता, आज भी ज्यादातर यह असर बरकरार है। ऐसे मे हिन्दी बेल्ट ही भाजपा को सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। इस बेल्ट मे खासकर युपी मे मायावती और अखिलेश के गठबंधन के बावजुद भाजपा जिती इसको जाति के उपर उठकर जनता वोट किए ऐसा कहा जाता है यह सच नही है, बल्कि भाजपा ने जातियों का ही इस्तेमाल किया है। भाजपा ने उपजातीयों के 33 अलग – अलग सम्मेलन किए, मायावती के दलित जातियों के इकट्ठा वोट को उपजातियों के नेताओं को खड़ाकर और उन्हे मायावती से तोडकर टुकडो–टुकडो मे बॉंट डाला और हर टुकडे से सौदा कर अपने से जोड दिया। मायावती को केवल जाटव के एक टुकडे तक सिमित कर डाला। यादवों की उपजातियों को भी इसी तरह कर डाला। भाजपाने जातियों से परे जाकर काम नही किया बल्कि जातीयों को और टुकडो मे विभाजित कर (उपजातीयों के प्रतिकों को उछालकर) ब्राम्हणवाद की निंव और मजबूत की। यह सारा राजनीतिक खेल ब्राम्हणी हिन्दू फासीवादी राज फिर एक बार पाँच साल लाने के लिए सत्ताधारी वर्ग ने खेला और उसमे वे सफल हुए। अब पाँच साल फिर शोषण और दमन का दौर जोरो से चलेगा। मजदूर, किसान वर्ग की हालत पस्त होगी। अर्थव्यवस्था और बर्बादी के तरफ धकेली जायेगी यह निश्चित है। शिक्षा मे

अवैज्ञानिक ब्राम्हणवादी ढकोसले के सिलॅबस के साथ व्यापारीकरण की मार झेलनी पड़ेगी। स्वास्थ का बाजार सरकारी योजनाओं से फुलेगा और निजी कंपनियाँ खुब कमायेगी। खनिज संपत्ती की लुट तेज होगी और आदिवासी और अन्य वन निवासीयों का भारी विस्थापन तय है। वैज्ञानिक विचार वाले, जनवादी विचार वाले, जनता के पक्षधर बुध्दिजिवीयों को देशद्रोही, देशविरोधी करार देकर जेल मे डालना या चुप कर देना तय है। मोदी को वोट देनेवाली जनता भी बहुत जल्द महसूस करना शूरु कर देगी कि उन्हे फिर एक बार ठगा गया है। पिछली बार भ्रष्टाचार के विरोध मे अच्छे दिन दिखाने के नामपर ठगाया था, इस बार देशभक्ति और देशपर खतरे का कृत्रिम हवा बनाकर देशरक्षक हिरो के रुप मे खुद को पेश कर मोदी ने ठगाया है। यह समय की माँग है कि कबतक हम ठगते रहेंगे? हमे चुनावी दौर मे प्रचार के जोरपर बनने वाली हवा के आधार पर अपना मत नही बनाना है बल्कि राजनीतिक पार्टीयों और नेताओं का समग्र चरित्र और समग्र कार्य को देखकर, उसकी करनी और कथनी के अंतर को पहचानकर एक सही राजनीतिक चेतना विकसित करनी है। चुनावी पार्टीयों के लिए सोच का दायरा सिमित ही रहता है, वह जातियों के जोड तोड, दलाल नेताओं और उनके गुटों की जोड तोड और वोट के अंकगणित के विभाजन और जोड पर ही केन्द्रीत होकर राजनीति करते है ऐसी राजनीति भाजपा के मजबूत संगठन और फासीवादी राजनीति का ना जवाब हो सकता है, ना ही मुकाबला कर सकते है और ना इससे कुछ नया और अच्छा निकलने की उम्मीद कर सकते है। ब्राम्हणी हिन्दू फासीवादी राज का जवाब केवल देशव्यापी जनआंदोलन के उभार के व्दारा ही दे सकते है। केवल इसके लिए जनचेतना विकसित करके ही एक राजनीतिक विकल्प खड़ा कर सकते है। इसलिए भाजपा के प्रतिगामी राष्ट्रवाद के खिलाफ सर्व संस्कृतिक समावेशी राष्ट्र भावना जो समानता और विश्व बंधुभाव के साथ जुडी हो निर्माण करना चाहिए। समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष मुल्य ही पुरोगामी राष्ट्रभावना निर्माण कर सकती है। इसलिए ब्राम्हणी हिन्दू फासीवाद के खिलाफ एक देशव्यापी संयुक्त मोर्चा इस मुल्य को इमानदारी से मानने और अमल करने वालों का बनाना समय की माँग है। ✶

(भारत मे दो राजनीति ... पेज नंबर 3 से) **जनता को ठगाते हुए जुल्म, शोषण और लुट करने वालों की राजनीति दुसरी किस्म की राजनीति है, चुनावी राजनीति इनकी ही राजनीति है। संक्षिप्त मे कहा जाय तो लड़ाई की राजनीति और चुनाव की राजनीति।** देश मे यह दो राजनीति चल रही है। हम लड़ाई की राजनीतिक दृष्टी से चुनाव की राजनीति को देखेंगे।

भारत के चुनावी दंगल को देखने के दो प्रमुख नजरिये है। एक वह है जो सत्ताधारी वर्ग दिखाता है और ज्यादातर उसी दायरे मे देखते है और विश्लेषण करते है। यानी वह तरिका जो सही मे चुनाव से हार जीत जो होती है, वह सत्ता बदल की हार जीत होती है। दुसरा नजरिया है मौजुदा राजनीतिक ढाँचा मे जो चुनाव की मौजुदा पध्दती है उसे सत्ताधारी वर्ग के बिच सत्ता संभालने के लिए जो स्पर्धा है उसे निर्धारित करने के लिए तय की गई पध्दती समजते है, इससे सत्ताधारी वर्ग मे कोई बदल नही होता है, सत्ताधारी वर्ग का ही कोई न कोई गुट सत्तापर बैठता है।

चुनावी दंगल मे हिस्सा लेने वाली मौजुदा पार्टीयों मे तीन किस्म की पार्टीयाँ है। एक सिधे कट्टर हिन्दू पंथी, दुसरी नरम हिन्दू पंथी तथा तीसरी धर्म निरपेक्षता का चोला पहने, जनवादी, समाजवादी और साम्यवादी का चोला पहनी हिन्दू पंथी के साथ मिक्श्चर धर्मो की पंथी। राजनीतिक विचारधारा के तौर पर तीनो ब्राम्हणवादी विचारधारा का अनुसरण करते है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई घोषित रुप से करते है तो कोई अप्रत्यक्ष रुप से करते है। चुनाव लड़ना ही मुख्य उद्देश रहने के कारण वोट बटोरने के लिए बहुसंख्य का तुष्टीकरण जरुरी है। इसलिए हिन्दूधर्म की धार्मिकता के आडे कोई नही जाना चाहता। यही मुख्य बिंदू बन जाता है यह फर्क करने का कि क्या ऐसी पार्टीयाँ भारत के समाज का विकास कर सकती है? यदी हम समाज का विकास का मतलब यह समजते है कि सारे मानव को स्वातंत्र, समता, न्याय और भाईचारा के तरफ ले जाना चाहते है। एक तरफ वोट बटोरना है और दुसरी तरफ साम्राज्यवाद, दलाल नौकरशहा पूँजीपति और जमीनदार वर्ग की सेवा मे राज चलाना है। राज चलाने का विकसित तरिका यह है कि जनता को राज्यसत्ता

के खिलाफ एक नही होने देना है। भारत मे इसके लिए जो नीति है उसे साम, दाम, दंड, भेद नीति कहते है। यह नीति जिस विचार के आधार पर खड़ी है वही ब्राम्हणवादी विचारधारा है। चाहे सोच समजकर हो या सिस्टम का हिस्सा बन जाने के कारण हो जब यह चरित्र राजनीतिक पार्टीयों का है तब चुनाव से सत्ता बदलती है यह समजकर विश्लेषण करना खुद को धोखा देने जैसा है। एक चर्चा ऐसी भी है कि चुनाव यह एक जनसमर्थन नापने का माध्यम है। फिर जबरदस्त जनसमर्थन वाले संग्रामी नेताओं की चुनावों मे हार क्यों होती गई?

हर मसले को समय और काल के दायरे मे देखना होगा। पूँजीवाद के काल मे आर्थिक संकट का समय चल रहा है। इसमे सत्ताधारी वर्ग को न केवल अपनी सत्ता बचाने की पड़ी है बल्कि पूरी पूँजीवादी व्यवस्था को बरकरार रखना है। **पूँजीवादी संकट बढ़ेगा तो शोषण और दमन बढ़ेगा, शोषण और दमन बढ़ेगा तो विद्रोह होगा, विद्रोह को सही दिथा मिलेगी तो क्रांति होगी, क्रांति होगी तो पूँजीवाद खत्म होगा और समाजवाद उसकी जगह लेगा। इससे बचने का पूँजीवादीयों के पास जो रास्ता है वह है फासीवाद।**

दुनिया मे पूँजीवाद को राजनीतिक स्थायित्व सबसे ज्यादा सामाजिक जनवादीयों टाईप के सरकारों ने दिया है। भारत मे भी नेहरु के समाजवादी ढकोसले पर काँग्रेस लंबे समय तक साम्राज्यवादीयों की भारत मे सेवा करती रही है। जब–जब पूँजीवाद संकट मे आया है तब–तब उसकी राजनीतिक परिणिती फासीवादी राज लाने मे हुई है। भारत मे मोदी जैसे फासीवादी नेता के नेतृत्व मे दोबारा सरकार बनाना यह सम्राज्यवादीयों की जरुरत है। उन्हे ऐसे कठोर निर्णय करने है जो जनता के विरुध्द है, शोषण बढ़ाने वाले है ऐसे समय ऐसी ही कठोर राजनीतिक व्यवस्था चाहिए जो निर्दयता से खुल्लमखुल्ला जनता के अधिकारों को दबाएँ और यह करते समय जनता का समर्थन भी हासिल हो। यह देशभक्ति, सुरक्षा, धर्म, संस्कृति या ऐसे भावनात्मक मुद्दे जिनपर बहुसंख्य जनता को मंत्रमुग्ध कर बहला जा सके सामने लाकर जनमत तैयार किया

जाता है। ऐसे सारे पहलुओं को समेटकर राज चलाने के लिए पूँजीवाद के रहनुमा साम्राज्यवादी शक्तियों को मोदी से बढ़कर चुनावी दंगल मे कोई और नही है। इस सत्ताधारी वर्ग की जरुरत के अनुसार जो योजना बनाई गई उसीके अनुसार चुनाव के नतीजे है, इसमे अचरज की कोई बात नही।
चंद टुकडों पर गदगद होकर खुषीयाँ मनाने वाले सरकार की दुहाई देते है। उनका कहना है कि अमीर यदी अधिक अमीर हो जायेगा तो गरिबों को भी कुछ तो लाभ मिलेगा। कुछ मिलने को ही धन्य समजने वाले बुजदिली को आधार मुहैया करते है। यह बुजदीली इच्छा, आकांक्षा और सपनों को मार देती है, हालात से समझौता करने पर मजबूर कर देती है, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने से रोकती है। ऐसे बुजदील, कमजोर तथा इरादों और विचारों मे बौने किस्म के लोंगों की आधी–अधुरी खुशहाल जमात दलाल पूंजीवाद ने भारत मे पैदा की है। इस तबके को देखकर निचेवाले आह भरते है, उन्हीके जैसा होने की तमन्ना लेकर उनके जिंदगी की जद्दोजहद चलते रहती है। वहीं यह आधा–अधुरा खुशहाल तबका निचेवालों के तरफ देखकर दिली खुषी महसुस करता है कि वह उनसे बेहतर जी रहा है।

'मै किसी से तो उपर हुँ' इससे मानसिक संतोष पाकर जीने के सामाजिक मानसिकता के बंधनों मे अपने आपको बाँध लेना यह हजारो साल से चली आ रही जातीय सिस्टम का गुणधर्म है जो आज भी आधुनिकता के साथ नये रंग मे अपने आपको ढालकर सिढ़ी दर खुषहाल मानसिकता के रुप मे पनप रहा है। यह मानसिकता भारतीय लोगों के डिएनए मे बस गई है। दुसरी और एक मानसिकता है जो दुसरों को नुकसान होने पर खुषी महसुस करना, भलेही उसमे खुदको कोई भौतिक प्राप्ती न हो। यह मानसिकता हजारों सालों से चली आ रही जातीयता की भौतिक वास्तविकता से निर्माण हुई है। यदी इसे उत्तेजना दी जाए तो यह उन भौतिक वास्तविकताओं पर भी हावी हो जाती है जो शोषण, उत्पीड़न और दमन के रुप मे सत्ता ने निर्माण की है। यह उत्तेजना निर्माण करना और लंबे समय तक बनाए रखने के लिए सत्ताधारी वर्ग को आधुनिक संचार तंत्र का बहुत उपयोग हो रहा है।

भारतीय मानसिकता या युं कहे तो धार्मिक–जातीय मानसिकता जुल्म

के खिलाफ आवाज उठाने नही देती। जो कुछ उसके साथ हो रहा है वह नसिब का खेल समजकर सहते रहता है। दुसरा यह कि जब–जब जुल्म होगा तब–तब भगवान अवतार लेकर आयेगा और सारे दुख दुर करेगा। तो खुद कुछ करने की आवश्यकता को नकारता है जो भी है कृष्ण करेगा। अवतार लेने की आध्यात्मिक भावना हिंदू धर्म का अविभाज्य अंग है।

कॉंग्रेस के कार्यकाल मे भ्रष्टाचार का खुल्लमखुल्ला बोलबाले के नकारात्मक मामले को बड़े प्रश्न के रुप मे और मोदी अवतार पुरुष के रुप मे सामने रखा गया याने राजनीतिक ब्रँड बनाया गया और बहुत योजनाबध्द रुप से इस ब्रँड की महत्ता को बनाये रखा गया है। साम्राज्यवादीयों की मोदी ब्रँड यह दस साल की परियोजना है, जो कई बार मोदी के मन की बात मे उन्होने खुद जाहिर की, जब कोई उनसे पुछते कि वह प्रधानमंत्री बनना चाहते है तो मोदी उत्तर देते की 2024 के बाद की सोचों। वास्तविक रुपसे देखा जाय तो राजनीतिक सिस्टम मे एक व्यक्ति का मामले का प्रश्न नही रहता है। सत्ताध ारी एक वर्ग होता है। वह यह सिस्टम चलाते है। उसमे उन्हे जैसे लोगों की आवश्यकता होती है वैसे लोगों को वह सत्ता संभॉंलने लाते है। भारत के नौकरशाही का वह उपरी तबका, साम्राज्यवादी और उनके दलाल शाशक वर्ग व्दारा चिन्हीत, प्रशिक्षित, निर्देशित और नियंत्रित होता है, वह शाशक वर्ग के लिए समर्पित होता है। उनके टॅलेन्ट को वह पूँजी की सेवा और पूँजीपति वर्ग के मुनाफे के लिए इस्तेमाल करते है। यह नौकरशाही का तबका ज्यादातर खुद भी पूँजीपति वर्ग का होता है या चंद जो उसमे जाते है वह जल्दी ही पूँजीपति वर्ग के हो जाते है। यह केवल नीतियाँ बनाने और अमंल करने का अधिकार ही नही रखते बल्कि जिसको जिताकर लाना है उनका चुनावी व्यवस्थापन भी यही कर रहे है।

'हिन्दूत्व याने राष्ट्रीयत्व', 'भारत माता की जय', 'वंदे मातरम्' इन नारों के इर्द गिर्द दिमाखी परवरिश की हुई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिगामी राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं की कतार जब ऐसे चतुर व्यवस्थापकों की योजनाओं को अमलीजामा पहनाने के लिए मौजुद हो तब यह जित यकिनी तौर पर हकिक़त बन जाती है। ब्राम्हणी हिन्दू फासीवादीयों के पास मौजुद

संगठन की शक्ति को मोदी सरकारने पाँच साल मे और मजबूत बनाया। सत्ता के व्दारा ऐसा सांगठनिक ढाँचा इसिलिए पाल पोसकर रखा जाता है कि वह संकट काल मे काम आ सकें। महात्मा गांधी की हत्या के बाद, आरएसएस पर बॅन लगने के बाद, और समय–समय पर बॉम्ब ब्लास्ट मे साध्वी प्रज्ञा ठाकुर से लेकर पुरोहित तक आंतकी होने के सबुत सरकारी संस्था व्दारा पेश किए जाने के बाद भी यह संगठन को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। यह कॉंग्रेस कार्यकाल मे ही फला फुला और व्यापक हुआ। जीवनभर कॉंग्रेसी रहे प्रणव मुखर्जी बड़े अदब के साथ आरएसएस के कार्यक्रम मे जाकर उसको मान्यता देते है। देहरादुन मे जैसे नौकरशहा निर्माण करने का सरकारी स्कूल है, वैसे ही भविष्य मे निर्माण होने वाले राजनीतिक नेता, कार्यकर्ता और नौकरशहा यह दिमाखी तौर पर ब्राम्हणवादी बनाने का काम आरएसएस की शाखाओं मे किया जाता है। ब्राम्हणवाद सत्ताधारी वर्ग का विचार है इसके तहत आरएसएस रंगरुटों को तैयार करता है यह एक अशाशकिय किंतू शाशन को प्रभावित करनेवाली और शाशन के पूर्ण सहयोग से चलने वाली संस्था है। यह अपने आप मे एक शाशन जैसी ताकत रखता है। यह सबको देखकर राजनीतिक सुझबुझ वाला कोई भी इतना तो कह सकता है कि भाजपा और कॉंग्रेस दोनो एक ही थाली के चट्टे बट्टे है। तो आम जनता को क्या फर्क पड़ता है की मोदी जिते या राहुल गद्दीपर बैठे? नीतियाँ बदलने वाली नही है, जनता के जीवन मे कोई बुनियादी बदलाव आनेवाला नही है।

इसलिए झुठे आस पर जीना छोडना है, सच्चाई का सामना करना है। सच्चाई यह है कि मोदी और गांधी की राजनीति जनता की राजनीति नही है। शोषित जनता ने इसलिए यह जानना जरुरी है कि किस राजनीति को हमने स्विकारना है? लड़ाई की राजनीति या चुनाव की राजनीति? चुनाव की राजनीति झुठ है, फरेब है, धोखा है, यह सत्ताधारी वर्ग और उनके चमचों की राजनीति है। बुजदील, कमजोर तथा इरादों और विचारों मे बौने किस्म के लोंगों की आधी–अधुरी खुशहाल जमात ही इसके गुण गा सकते है। शोषित जनता और जनता के पक्ष मे रहने वाले जनवादी, क्रांतिकारी बुध्दिजिवीयों की राजनीति लड़ाई की राजनीति है। जो लड़ाई के राजनीति के पक्षधर है उन्हे

अपने रंगरुट और संगठन मजबूत और विस्तार करने ध्यान देना चाहिए। तैरता हुआ छोटा समुह हर जगह रहता है जो हवाओं के झौंको के साथ इधर उध ार जाता है। चट्टान की तरह मजबूत इरादों वाले बुलंद किरदार लड़ाई की राजनीति के असली योध्दा होते है। 17 वी लोकसभा के परिणामों से एक बात अच्छी हुई कि मध्यमार्गीयों का भ्रम का बुलबुला फुट गया। ब्राम्हणी हिन्दू फासीवादी ताकतें स्पष्टतौर पर सत्ता के साथ सामने है, इसलिए अगर भारत को बहुसंस्कृतिय, और विविधताओं से भरा, न्याय, सबको स्वातंत्र, समता और भाईचारा वाले महान देश के रुप मे खड़ा करना है तो संघर्ष के राजनीति के सिवा और कोई विकल्प नही है। ✶

(मोदी हारा ..... पेज नंबर 2 से) हुए अपने आपको महान बनाने की बेशर्मीभरी नुमाईशों और इस बेइज्जतीसे लगातार शर्मसार होता भारत ऐसे निचले दर्जे के नेताओं के गिरोह से पिंड छुडाना चाहता था। एक तरफ आंबेडकर के प्रतिको को उछालना और दुसरी तरफ दलितों को पिटाना, एक तरफ बेटी बचाओ कहना और दुसरी तरफ बलात्कार मे बढ़ौती, एक तरफ सांप्रदायिक सौहार्द की बात और दुसरी तरफ मुस्लिमों का कत्ल करना, एक तरफ काश्मिरियत की बात और दुसरी तरफ काश्मिरियों की लगातार हत्याएँ करना, एक तरफ 'सबका साथ सबका विकास' कहना और दुसरी तरफ अडानी, अंबानी की तिजोरीयाँ भरना, भारत को इस दोगलेपन से घिन आने लगी थी, वह इससे मुक्ति चाहता था। भारत दलाली, नकल और चाटुकारिता वाले 'मेक इन इंडिया' की जगह अपनी प्रतिभा, मेधा और सामर्थ्य के आधार पर आगे बढ़ने के अवसर चाहता था। भारत हिन्दूत्व यानी ब्राम्हणी राष्ट्रीयत्व की जगह बहुसांस्कुतिक राष्ट्र गौरव के साथ विश्वबंधुत्व वाले दृष्टीकोण के लोग देश का नेतृत्व करे ऐसी चाहत पाले था। हिन्दू आतंकियों के संरक्षको की जगह धर्मनिरपेक्षता के मुल्य के पालनकर्ता चाहता था। उपजातियों और पहचान की राजनीति को उछालकर समाज का सुक्ष्म विभाजन और गहरा करने वाले घोर जातीयवादी चालाख राजनेताओं के बजाय जाति निर्मुलन के लिए लड़ने वाले खुले और जनवादी दिमाख के राजनेता चाहता था। वह स्वातंत्र, समता, भाईचारा, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी और समाजवादी मुल्य वाला भारत देश चाहता

था ताकि, हर नागरिक देश मे सुकुन की जिंदगी बीता सकें, आजादी की सांस ले सकें। यह सब चाहत अपेक्षाएँ और सोच भारत ने 17 वी लोकसभा के चुनाव मे दाँव पर लगाई थी। उसकी सोच थी कि चुनाव के जरिए वह ऐसी सरकार लायेगा जो उसे वह सब कुछ देगी जो वह चाहता है। पर वह हार गया। वह समज नही पाया कि उसकी हारने की नियति पहले से तय की जा चुकी थी। उसे हारना ही था क्योंकि जितने वालों ने उसके खिलाफ उसे हराने की जबरदस्त रणनीति बुनी थी अपितु यह रणांगन भारत का था ही नही।

'भारत' यह और कोई नही बल्कि देश की आम जनता है, यह देश की शोषित जनता है जो 'भारत' नाम की संज्ञा मे समाविष्ट होकर चुनावी दंगल मे प्रतिनिधित्व किया और हार गया। यह प्रातिनिधिक विशेषण या लेखन शैली की अलंकारिकता भले ही लगे किंतू यह वास्तविकता से परे भी नही है। क्या भारत की उपरोक्त अपेक्षाएँ और सोच वास्तविक नही है? क्या यह भारत की जनता की आवश्यकता नही है? क्या राजनीतिक सत्ता का कर्तव्य यह नही होना चाहिए कि वह जनता की आवश्यकता की पुर्ती करें? भारत की सोच और उसने सामने रखी आवश्यकताएँ एकदम सही है, पर उसका यह सोचना गलत हो गया कि चुनाव के जरिए उसको यह सबकुछ मिल जायेगा, उसका यह मानना गलत है कि चुनाव से जनता के हित की सरकार आती है। दरअसल राज्यसत्ता की समजदारी मे ही भारत गलती कर रहा है। उसे यह समजना होगा कि सत्ता किसी वर्ग की दुसरे वर्ग पर तानाशाही होती है। भारत देश मे सत्ता साम्राज्यवादीयों के दलालों यानी दलाल नौकरशहा पूंजीपति एवं जमीनदार वर्गों की है और चुनाव प्रक्रिया पुरी तरह उसी के कन्ट्रोल मे है, चुनाव के जरिए जो भी चुनकर आए वह शाशक वर्ग के प्रतिनिधि होते है। यह शाशक वर्ग विकास के सब्ज बाग दिखाकर, जनता की समस्या को उछालकर ऐसा दिखावा करता है मानो वह सबकुछ ठिक कर देगा, यह उसकी राजनीतिक चाल है, इससे वह जनता को भ्रम मे रखकर अपना राज चलाता

है। भारत को अब राजनीति के वह सारे गुर सिखने होगे, कोरी आशा रखने से काम नही चलेगा। लक्ष्य सही रहने से मात्र नही होता, उसे हासिल करने के लिए साधन और प्रक्रिया भी सही होनी चाहिए तब ही अपेक्षित नतिजे मिलेंगे। चुनाव मे पक्ष और विपक्ष और चुनाव के बाहर संविधान के ढकोसले को पवित्र मानकर गुमराह करने वाले मध्यममार्गीयों के परे, असल मे 'भारत' की राजनीति होनी चाहिए। भारत को विजयी होना है तो अपने साधन याने जनता के लिए इमानदारीसे कार्य करनेवाले मजबूत लड़ाकू संगठन और व्यापक जनसंघर्ष और सशस्त्र संघर्ष के समन्वय का रास्ता अपनाना होगा। भारत के विजयी होने की गॅरंटी उसके मजबूत सशस्त्र संगठन याने जनसेना निर्माण मे है। भारत के पास प्रचंड शक्ति है, पुरखो की लड़ाई का गौरवशाली अतित भी है, जो आत्मविश्वास से लबालब कर देता है, भारत अपने आपको पहचानो तो विजय तुम्हारे कदम चुमेगा। उम्मीद है 17 वी लोकसभा के चुनाव से सबक लेकर भारत सही मार्ग चुनेगा।

पीएलजीए के साहसिक कार्रवाई का अभिनंदन!

1 मई 2019 को गडचिरोली जिले के कुरखेडा तहसिल के अंतर्गत जांभूळखेडा गांव के पास महाराष्ट्र के कुख्यात कमांडो पुलिस सी–60 की क्विक ॲक्शन टीम के 15 जवानो को खत्म कर गडचिरोली जिले मे चल रहे सरकार के आतंक का करारा जवाब दिया। सरकार की ओर से झुठे मुठभेडो मे हत्याएँ करना, जनता पर जूल्म करना, आदिवासीयों को जल–जंगल और जमीन से बेदखल कर दलाल कंपनियों को खदान खोलने देना और जनता को विस्थापित करना, आदिवासी संस्कृति का नाश कर ब्राम्हणीकरन करना इसके खिलाफ निरंतर चल रहे जनयुध्द मे जनता की ईच्छा और पीएलजीए समवेत सक्रिय किए गए प्रतिरोध का एक उन्नत प्रहार यह हमला है।

दर्शन दिग्दर्शन

'सबका साथ और सबका विकास' यह पाखंड है, जनता को बेहाल और पूंजीपतियों को मालामाल करने का यह फंडा है!

साम्राज्यवादीयों, दलाल पूंजीपतियों और उनके दलालों को मालामाल करने वाले इस प्रधान स्वंय सेवक की छवी नंबर एक बनाना सत्ताधारी वर्ग की जरुरत थी। इसके लिए उनकी ब्राम्हणवादी मक्कारी और पाखंड को दर्शन बनाकर परोसा गया। पर पिछले पाँच साल मे भारत की जनता को यह अच्छी तरह समजमे आ गया है कि, प्रधानमंत्री नरेंन्द्र मोदी झुठ बोलने मे नंबर एक पर है। दिखावा करने मे नंबर एक पर है। दलाल पूंजीपतियों की संपत्ती बढ़ाने मे नंबर एक पर है। जनता का शोषण करने मे, दहशत फैलाने मे, विरोधियों को धमकाने मे और उनकी हत्या करवाने मे भी नंबर एक पर है और जनआंदोलनों को कुचलने मे भी नंबर एक पर है। साम्राज्यवादी सुचना तंत्र ने मोदी के तमाम पाखंड को 'सबका साथ सबका विकास' मे गढ़कर उसे नंबर एक बना दिया।

मोदी सबका साथ सबका विकास को उसकी फिलॉसॉफी कहता है। यह सुनने को अच्छी लगती है। पर क्या वाकेई इसमें सबका विकास हो सकता है? मोदी के अनुसार अंबानी और एक आम किसान उन सबका उसको साथ चाहिए और उनका विकास भी होगा। मतलब अंबानी जिसका पहले से ही विकास हो चुका है उसका भी और विकास होगा और किसान का भी विकास होगा। तो मोदी के विकास की इस गंगा मे कौन कितना हाथ धोयेगा? यदी मान लिया जाय कि अंबानी और किसान का पहले जिस रेट से विकास होता था वैसाही होगा तो इसका सिधा मतलब है कि अंबानी और किसान के बीच की गॅप कभी नही मिटेगी इसकी मोदी गॅरंटी दे रहे है। इसको हम एक

साधारण उदाहरण से देख सकते है। क्या कभी शेर और बकरी एक घाट पर पानी पी सकते है? इसका कोई भी उत्तर देगा कि नही ऐसा कभी नही होता। पर यदी शेर और बकरी एक घाटपर अचानक आ जाय और पानी पिने लगे तो क्या होगा? एक बच्चा भी इसका उत्तर देगा कि शेर बकरी को खा जायेगा। तब मोदी के विकास की गंगा के घाटपर अंबानी, अदानी, टाटा, मित्तल जैसे शेरों के झुंड की झुंड है ऐसे मे किसान और मजदूर जैसे बकरे उस विकास के घाट पर सिर्फ कटने के सिवा कुछ नही हो सकता। मोदी के पिछले पाँच साल मे किसानों की तीनगुना ज्यादा बढ़ी आत्महत्या, बेरोजगारी न`धारण किया विकराल रुप और प्रचंड रुप से बढ़ी अंबानी, अदानी जैसों की संपत्ती इसका सबूत है। वास्तविक रुप से मोदी चाहे जो फिलॉसॉफी बताए वह अंत मे सत्ताधारी वर्ग की सेवा के लिए रचा गया फंडा ही होता है। आरएसएस की ब्राम्हणवादी विचारधारा के तले पले बढ़े मोदी इससे बाहर कैसे हो सकते है? जनता को लुभाने के लिए जो भी नारा गढ़े पर ब्राम्हणवाद तो सत्ताधारी वर्ग की सेवा के लिए ही है। मोदी को जनता केवल वोट के लिए साथमे चाहिए विकास तो केवल भारत के दलाल नौकरशाह पूंजीपतियों का हुआ है। किसान, मजदूर, छोटे उद्योग धंदेवाले कंगाल हो गए है। उच्च शिक्षा लेने के बाद यदी कोई पकौडे बेचेगा तो यह रोजगार नही उसका अपमान होगा। विकास का आलम तो यह है कि पकौडे भी नही बिक रहे। सबका साथ सबका विकास ने बेरोजगारी रेकॉर्ड स्तर पर पहुँचा दी है। मोदी का यह विकास का फंडा जनता की तकलिफों को ढ़कने का वैचारिक जुमला है। वर्गसंघर्ष को बोथरा बनाने के लिए जनमानस पर चलाया जा रहा मनोवैज्ञानिक हथियार है। वर्गिय समाज मे जहाँ असमान विकास है, जहाँ व्यापक जनता को जातीय बंधनो मे जकडकर विकास के साधनो से जबरदस्ती वंचित रखा गया है, जहाँ केवल एक प्रतिशत धनवानों के कब्जे मे देश की 75 प्रतिशत संपत्ती है, सत्ता, समाज, संस्थानों और साधनों पर जहाँ ब्राम्हणवादीयों का कब्जा है वहाँ सबका विकास का नारा एक बोगस नौटंकी के सिवा कुछ नही है। व्यापक जनता का विकास करना है तो उन कारणों को नष्ट करना जरुरी है जिनके कारण व्यापक जनता का विकास बाधित हुआ है या जो जिम्मेदार

है व्यापक जनता के विकास को रोके रखने के लिए। इसका सिधा अर्थ है दलाल नौकरशहा पूंजीपति और जमीनदार वर्ग के पास जो पूँजी, संपत्ती है उसे जप्त कर व्यापक जनता के हित मे उपयोग करना। साधनों पर व्यापक जनता का हक बहाल करना। यह तब ही संभव है जब व्यापक जनता के हाथ मे सत्ता हो। मोदी सबका विकास के नामपर उन्ही लोगों का हित साध रहे है जो पहले से ही विकसित है। मोदी का नारा 'सबका साथ सबका विकास' यह पाखंड के सिवा और कुछ नही।

ब्राम्हणी हिन्दू फासीवादी राज का पाखंडी विचार सबका साथ सबका विकास और उसके अंतर्गत दिया गया 'नया भारत' का नारा यह जनता के लिए धोखा, दमन, लुट और शोषण के सिवा दुसरा कुछ नही। मोदी का नया भारत याने ब्राम्हणवाद+मेक इन इंडिया+डिजिटल इंडिया+'समाधान' नाम से बनाई गई नई दमन नीति है। अर्थाथ पुलिस अर्धसैनिक बलों व्दारा क्रांतिकारी और जनआंदोलनों पर क्रूर दमन, हिन्दू फासीवादी संगठनों के आंतक से सामाजिक दहशत बनाकर रखना ताकि मुल समस्यापर जनता ध्यान ही ना दे और गोलबंद ना हो सके, ऐसे राजनीतिक कन्ट्रोल मे विदेशी कंपनियों व्दारा भारत मे कलपुर्जे लाकर असेम्बल करना और खनिज संपत्ती को लुटने के लिए, देश के व्यापार मे बड़ी विदेशी कंपनीयों को घुसने के लिए रास्ता खुला करना यह है। सुरक्षा के नामपर डिजिटल उपकरनों की प्रचंड खरेदी कर विदेशी डिजिटल कंपनियों को बड़ा बाजार उपलब्ध करना और उन उपकरनों के व्दारा भारत की जनता के जनवादी हकों को कुचल देना। भारत के नौजवानों अपने देश के राज्यसत्ता की कमान जबतक इन लुटेरों के हाथ मे है तब तक न तो नौजवानों को उसकी काबीलियत के अनुसार सम्मानजनक रोजगार मिलेगा और न ही जनता के जीवन मे खुषहाली आयेगी और ना ही भारत स्वातंत्र, समता और भाईचारा का पालन करने वाला उचे मुल्य का देश कहलायेगा। इसलिए दलालों के हाथ से सत्ता और संपत्ती छिनकर देश के विकास मे लगाना ही उसका उत्तर है और इसको हासिल करने का मार्ग नवजनवादी क्रांति है।

इसलिए हर गांव मे, शहरों के मोहल्लों मे, कॉलेजों मे, होस्टलों मे,

कारखानों मे, खेतो–खलिहानों मे, ऑफिसों मे, विभिन्न सेवाओं मे लगे हुए विभागों मे अपने आप संगठित हो जाए। एक छोटे से विचार मंथन के गृप से शुरु कर फिर उसे अपने विचार को मानने वाले दोस्तों को जोडते जाए, अपनी–अपनी समस्या पर आवाज उठाते जाओ, अपनी समस्या की जड राज्यसत्ता के साथ जोडकर जनता को बताते जाओ, चाहे कहीं भी हो और किसीपर भी हो अगर अन्याय होता है तो उसके प्रतिरोध मे खडे हो, अपने पर आ गुजरने तक इंतजार मत करो, हमेशा शोषित जनता की तरफ से रहो, सत्ताधारी वर्ग का हर राजनीतिक कदम आपकी जिंदगी का फैसला करती है इसलिए उसपर जरुर प्रतिक्रिया दो। डिजिटल मिडीया 99 प्रतिशत मोदी का भक्त है, वे आपकी आवाज व्यापक जनता तक नही पहुँचायेंगे, वे तो सत्ता के संरक्षक है, इसलिए अपने साधनों को निर्माण करना होगा। सत्ता के आक्रमक प्रचार हमले से हमें विचलित नही होना चाहिए, झुठ के बलपर ज्यादा दिन राज नही चला सकते, अन्याय और शोषण से त्रस्त जनता निश्चित ही संगठित शक्ति बनकर उभरेगी। जो राजनीतिक चेतना से परिपक्व हो गया है उन्हे संघर्ष की निरंतरता देशव्यापी दावानल बनने तक जारी रखनी है। अपनी, आपकी और आपके जैसी ही अन्य नौजवानों की देशभर की आवाज भलेही अलग–अलग लगती हो पर ऐसी सभी आवाज नवजनवादी क्रांति के व्यापक संघर्ष का हिस्सा बन जाती है, यह आगे जाकर कभी न कभी समन्वित होकर क्रांति की एक ताकतवर भौतिक शक्ति बनेगी जो देश को साम्राज्यवाद और दलाल नौकरशाह पूंजीपतियों से मुक्त करायेगी, उनकी अरबों की संपत्ती को जब्त करके देश का सही मायनों मे विकास करेगी। नौजवानो के हाथ मे ही देश का भविष्य है। माओवादी पार्टी देश के नौजवानों के साथ है।

दंडकारण्य की क्रांतिकारी नेता कॉ. नर्मदा और वरीष्ट नेता कॉ. किरण की गिरफ्तारी की निंदा करों!

उन्हे बिना शर्त रिहा करने तथा उन्हे योग्य मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने संघर्ष करों!

वित्तरंग

तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था और तेजी से फैलती सामाजिक अव्यवस्था

तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था और जवाँ डेमोग्राफी की डिंगे हांकते–हांकते मोदी ने पाँच साल गुजार लिए। इन पाँच सालों मे दलाल मालामाल हुए और जनता कंगाल हुई। पूंजी निर्माण के नये कारकों पर ध्यान देने के बजाय जनता को और ज्यादा निचोडने मे ही अपने बनिया कौशल का इस्तेमाल करते रहे। उटपटांग निर्णयों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को बुरी तरह झकझोर दिया। मानव की जरुरत के लिए बाजार नही बल्कि बाजार की जरुरत के अनुसार मानव रहना इस नीति पर काम चल रहा है। और जो बाजार के लिए उपयोगी नही वह उनके दृष्टी से मानव ही नही। विकास नारा जितने भी जोर से बोला जा रहा है पर वह बाजार से हटकर नही है। साम्राज्यवादी और दलाल नौकरशहा पूजींपतियों का मुनाफा और उसके लिए बाजार का चक्र गतिमान करना इस मुल उद्देश को हासिल करने नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व मे ब्राम्हणी हिन्दू फासीवादी राज को सत्ताधारी वर्ग लेकर आए थे। मोदी उनके आंकाक्षा पर खरे उतरे है, भलेही इसके लिए उन्होने देश की अर्थव्यवस्था की ऐसीतैसी की हो, हजारो जनता को मौत के घाट उतारा हो, सामाजिक मुल्य की बली चढ़ाया हो या संविधान की धज्जीयाँ उडाया हो, सबकुछ माफ है क्योंकि वह दलाल पूंजीवाद का संकटमोचन है। पर इस हणुमान ने राजनीति, अर्थनीति, समाजनीति, संस्कृति सबको आग लगाकर रख दी है। इससे पहले कि सबकुछ जलकर राख हो जाए इसका बंदोबस्त करना जरुरी है। सत्ताधारी वर्ग का संकट टला नही है इसलिए उन्होने फिर एक बार मोदी को ही जिताकर लाया है। अब यह छुपा नही है कि भारत के चुनाव पुरी तरह सत्ताधारी वर्ग की कन्ट्रोल मे है और वे इसका इस्तेमाल करते हुए उन्हे जो सत्ताधिश चाहिए उन्हे जिता सकते है। मोदी की जित भारत की जनता के

लिए फिर एक बार आर्थिक संकट लेकर आई है वहीं पूंजीपतियों के लिए उनके संकट से बाहर निकलने के लिए कठोर जनविरोधी नीतियाँ बनाने वाली सौगात है।

मोदी के तथाकथित विकास को साकार करने वाले विदेशी 'पूंजी निवेश स्वरुप भगवान' को प्रसन्न करने के लिए ज्यादा उदारीकरण और ज्यादा निजीकरण महाआरती करते रहे। इससे फासीवादी राजनीति का बाजार गर्म रहा। इस बाजारु व्यवस्था मे राजनीति भी माल बन चुकी है। इसलिए उसे भी बाजार के वह नियम लागु होते है जो हर माल को होते है। चुनाव लडने का व्यवस्थापन के ठेके तो देशी विदेशी कंपनीयों को दिए जा रहे है, कल सरकार चलाने और कानून बनाने के ठेके भी यदी दिए जाय तो कोई अचरज की बात नही होगी। जरुरत ने बाजार खडा किया अब बाजार जरुरत को निर्माण कर रहा है। जनता की क्रयशक्ति बढ़ने से बाजार बढ़ता है, मोदी ने खर्च करने की भारतीय मानसिकता को बदलने के लिए मजबूर कर दियाद और ज्यादा से ज्यादा बाजार के तरफ खिंच लाया है। जनधन योजना, डीजीटालाईजेशन, और उपभोक्तावादी उन्माद गांवों तक फैला दीया है। इससे भविष्य के लिए बचत रखते हुए हाथ खुला करने की मानसिकता टुट गई है और पास मे है वह पूरा खर्च करों, बल्कि अपनी हैसियत से भी ज्यादा खर्च करो ऐसी मानसिकता को स्थापित किया जा रहा है। 'ओव्हर ड्रॉफ्ट टेंडेंन्सी ट्रेंड' यह बैंको तक ही सिमित नही रही, बल्कि क्षमता से ज्यादा उधार लेकर खर्च करने की प्रवृत्ती के रुप मे भी दिख रहा है, हर मामले मे भारी रिस्क लेकर व्यवहार करने के रुप मे प्रतिबिंबीत हो रहा है। जिससे किसी भी वक्त दिवालिया होनेकी संभावना बनी रहती है। इस बाजार उन्माद ने अमीर और गरीब की खाई जमीन और आसमान जैसी बना दी है।

मोदी की आर्थिक नीतियों से अर्थव्यवस्था और जनता दोनो बेहाल : भारत 2.439 ट्रिलियन डॉलर के साथ विश्व मे छटी अर्थव्यवस्था बनी। इज ऑफ डुईंग मे प्रगती कर 130 से 100 पर पहुँचना, मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे अमिर की कतार मे 15 वे नंबर पर आ जाना, भारत मे अरबपतियों की संख्या बढ़कर 831 हो जाना, बडे–बडे हायवे और

उसपर आधुनिक तकनिक से पर्ची फाडकर टोल टैक्स कटाती मशीने, चौक से लेकर मंदिरो तक सीसीटीवी कैमरे, सब्जीपाला से काम्पुटर तक बेचने वाले मॉल्स, आयटी नेटवर्क, जीपीएस और ड्रोन के व्दारा निगरानी करती पुलिस यह इंडिया की तरक्की दिखाता है।

वहीं दुसरी तरफ गरीबी रेखा मे जीने वाले 79 प्रतिशत लोग(21.2 प्रतिशत 1.90 डॉलर मे और 58 प्रतिशत 3.10 डॉलर प्रतिदिन मे जीते है। गौरतलब है कि मुकेश अंबानी हर दिन 300 करोड रुपए कमाता है।),तीन गुना किसान आत्महत्या, 9.5 प्रतिशत बेरोजगारी (सरकारी आकडा), 65 करोड जनता मुलभूत सुविधा से वंचित रहना, हवा, पानी और अन्न श्रृंखला का भयानक प्रदुषण, 73 : संपत्ती केवल 1 : लोगों के पास जमा होना, मंहगाई 5. 7 से 6 प्रतिशत मे होना, राजकोषिय घाटा 3.5 प्रतिशत और चालू खाता का घाटा 2.5 प्रतिशत हो जाना, जीडीपी वृध्दी 2 प्रतिशत गिर जाना, रुपए का अवमुल्यन लगातार होकर वह 74 रुपए प्रति डॉलर हो जाना, बैंकों को नुकसान, छोटे और मझौले उद्योग बर्बाद हो जाना, विदेशी कर्ज 513 बिलियन डॉलर हो जाना यह भारत की दुसरी तस्विर दिखाता है।

चंद दलाल पूंजीपति के संपत्ती मे भारी बढोतरी को भारतीय अर्थव्यवस्था का तेजी से बढ़ना बताया जा रहा है यह एक छलावा है, वास्तविक रुप से अर्थव्यवस्था की हालत खस्ता हो गई है। और जनता मे भी भारी असंतोष और अव्यवस्था है। जीडीपी मे कृषि का हिस्सा 17.32 फिसदी था वह 14 पर आ गया है जबकि 47 फिसदी लोग इसपर निर्भर है, उद्योगों का 29.02 फिसदी से 26 पर जिसपर 22 फिसदी लोगों का रोजगार निर्भर है और सेवा क्षेत्र का 60 फिसदी है और 31 फिसदी लोग इसमे कार्यरत है। उद्योग क्षेत्र की विकास दर चार वर्षो मे 8.2 प्र.श. से 4.4 प्र.श., कृषि 4.2 प्र.श. से 2.1 प्र.श., चालू खाता घाटा 1.5 प्र.श. 2.5 हुआ है। करदाता की संख्या 50ः बढने का दावा किया जा रहा है पर राजस्व नही बढ़ा। सितंबर 2017 मे 92150 करोड रुपये था जो जनवरी 2018 मे 86703 करोड रुपये पर आ गया। 'एसबीआय इकोरॅप' के रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018–19 मे अप्रत्यक्ष टैक्स मे 90,000 करोड रुपए का घाटा रहने की संभावना है, जीएसटी का उदिष्ट 7.44 लाख करोड रुपए है पर

वह 6.78 लाख करोड रुपए से ज्यादा नही हो पाएगा। जीडीपी 7.5 का अनुमान लगाया पर 6.7 से आगे नही बढ पाया। 7.5 हासिल करना है तो औद्योगिक विकास दर 10 से 11 : चाहिए और कृषि विकास दर 4: चाहिए, जो नही है। एएसइआर रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत मे 59 : युवाओं ने कभी काम्पुटर पर काम नही किया और 64 : ने कभी इंटरनेट इस्तेमाल नही किया। फिर डेमोग्राफी की डिंगे मारने का क्या फायदा जब आधुनिक कौशल के लायक युवाओं को बना ही नही पाए? मोदी ने भाषणों से जनता को धोखा दिया, बडे दलाल नौकरशहा पूंजीपतियों को बहुत मुनाफा दिलवाया और भारत की अर्थव्यवस्था को बर्बादी के तरफ धकेल दिया है।

मनमोहनॉमिक्स का उन्नत रुप मोदीनॉमिक्स : मोदी–जेटली के सामने दो रास्ते थे 1. सरकारी निवेश बढ़ाकर घरेलू निवेश के सहारे अर्थव्यवस्था को बढ़ाना। 2. वित्तीय घाटा कम रखके विदेशी निवेश बढ़ाकर अर्थव्यवस्था को बढ़ाना। पहला रास्ता अचानक नही पकड सकते। दरअसल दोनो रास्ते अंत मे वित्त पूंजी की ही सेवा करते है फिर भी पहले के लिए घरेलू पूंजी निर्माण की वह पर्याप्त गति चाहिए जो घोषणाओं मे तो है पर धरातल पर कभी नही उतरती। लिहाजा मनमोहन ने जो रास्ता बनाया उसीपर मोदी–जेटली को चलना था। उदारीकरण तेजी से पर्याप्त नही किया जा रहा इसलिए साम्राज्यवादीयों ने खासकर अमेरीकन साम्राज्यवादीयों ने मनमोहन सिंग को हटाकर मोदी को लाया। अपेक्षा के अनुरुप मोदी ने बचे हुए संस्थानो मे शत प्रतिशत एफडीआय के दरवाजे खोल दिए। पर ट्रम्प आने के बाद संरक्षणवादी नीतियों ने खेल बिगाड दिया। पंच वार्षिक योजना बनाने वाले योजना आयोग की जगह 'नीति आयोग' लाकर नीतिगत देरी और अनिश्चितता और अस्थिरता निर्माण कर दी। उदारीकरण के समर्थक रहे चार ख्याती प्राप्त अर्थशास्त्री रघुराम राजन, अरविंद सुब्रम्हण्यम और अरविंद पनगाढीया और उर्जित पटेल इनकी बली अमेरिकन संरक्षणवाद के लिए चढ़ाई गई। इन चारों के रहने के बावजूद भी मोदी आर्थिक सलाह बिबेक देबरॉय और रतन वाटल से ही लेते थे और आज तो यह अधिकृत ही है। मोदी को संघ शाखाओं की तालिम लिए ऐसे लोग चाहिए जो ब्राम्हणवादी मक्कारी के साथ पूंजीवादी

अत्याधिक शोषण का मेल बिठा सके। जो जनता की क्रयशक्ति को निचोडकर दलालों के हाथ मे पूंजी का अत्याधिक केन्द्रीकरण कर सके और ऐसी नीतियाँ बनावें की इस अतिरिक्त निचोड को लोग विकास समज बैठे।

अर्थव्यवस्था मे इतनी अव्यवस्थता आई है कि वित्त मंत्रालय, प्रधानमंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार रहने के बावजूद भी 'प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद' का गठन सितंबर 2017 को करना पड़ा। नीतिगत अस्थिरता के कारण घरेलू कारोबार और निर्यात प्रभावित हुआ। कल कौनसी नीति और कौनसा नया ऐलान मोदी करेगा कोई भरोसा नही इससे छोटे और मझौले उद्योग जगत मे असंमजस और घबराहट का वातावरण बना रहा और वह बर्बाद भी हुए है। पर मोदी के नजदीक रहनेवाले और बडे दलाल पूंजीपतियों को इसका बहुत लाभ हुआ है। नोटबंदी, जीएसटी, ईवे बिल, विभिन्न किस्म के पंजिकरण से छोटे और मझौले कारोबार दिवालिया हुए। कंपनियाँ मजदूरों का जीएसटी रजी. किए बगैर काम नही देगी, छोटे कस्बों से आए कारागिरों का काम बंद हुआ। एक तरफ 20 लाख कारोबारीयों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन से बाहर बताया पर उनको आंतरराज्यीय कारोबार मे रजिस्ट्रेशन की अनिवार्य किया है उससे राज्य के बाहर कारोबार करने मे झंझट है, एक देश एक टैक्स का दावा झुठा हुआ। टैक्स चोरी कम करने के नाम पर प्रक्रिया इतनी जटील की गई की इसका पालन करना एक मुसिबत बन गई। बढ़ती अव्यवस्था का डॅमेज कन्ट्रोल करने बार–बार टैक्स घटाया। बगैर किसी नोटीफिकेशन से डयूटी ड्रा बॅक स्किम खत्म कर देने के कारण 20 प्रतिशत निर्यातकों ने डिलिवरी रोक दी है। निर्यात मे 50 से 70 प्रतिशत नुकसान हुआ। बैंको के कर्जो मे 50 प्रतिशत गिरावट है। नई परियोजनाएँ 21 प्रतिशत घटकर 637 रह गई है। मोदी की तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था मे कमतर निवेश, घटती कृषि विकास दर बर्बाद होत किसान, कर्ज उठान मे कमी, उद्योगो मे स्थापित क्षमता से कम इस्तेमाल, पॉवर प्लांटो की कमतर उत्पादन क्षमता, घटते रोजगार यह हो रहा है।

इसतरह भारत मे मोदी निर्मित पांच संकट इसप्रकार है :–1. आधी से ज्यादा आबादी गरिबी मे 2. कृषि समस्या 3. मैन्युफॅक्चरींग वृध्दी कमी 4.

व्यापार घाटा 1950 के बाद सबसे ज्यादा (चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा चीन के रक्षा बजट 60 अरब डॉलर के बराबर है। एक किस्म से कहा जाय तो चीन के साथ युध्द हुआ तो उसका सैन्य खर्च भारतीय बाजार वहन करेगा।) 5. बेरोजगारी जो इन चारों से निर्माण हुई। इससे और दो समस्या खडी हुई राजस्व और एनपीए।

विदेशी निवेश, निर्यात और राजकोषिय घाटा को नियंत्रण मे रखना यह विकास के मंत्र मनमोहन के भी थे और मोदी के भी रहे है (यह 80 के दशक से विश्व बैंक ने दिए हुए मंत्र है)। इन तीनो मोर्चे पर मोदी बुरी तरह फेल हो गए। फेल होने के सिग्नल दिखने से ही नोटबंदी, जीएसटी, कल्याण कार्यक्रमों मे डिजिटालाईजेशन और जनधन के व्दारा जनता से अधिक अतिरिक्त मुल्य निचोडा गया और जनता को कंगाल बना दिया। देशभक्ति के नाटक और पाकिस्थान को तथाकथित मजा चखाने के हव्वा मे आर्थिक लुट और बदहाली का यह विदारक दृष्य धुंधला कर दिया गया। अर्थनीति और राजनीति का घनिष्ठ संबध और उसका जनता के जीवन पर पडने वाला सिध्ा संबध इस बाबत की राजनीतिक चेतना का खालीपन ब्राम्हणी हिन्दू फासीवाद उसके व्दारा मनोवैज्ञानिक आक्रमक प्रचार से भर देता है और भ्रमित हुआ दिमाख कमल की बटन दबा देता है। कहीं–कहीं कोई भी बटन दबाने से कमल को ही जाता है। इसलिए चुनावों की जित–हार, देश के जनता की बदहाली या देश की अर्थव्यवस्था के बुरे हाल का प्रतिबिंबन या प्रभाव का प्रमाण नही हो सकता। यह प्रमाण जनता का जीवनमान से लगाया जा सकता, जनता की परेशानियों से लगाया जा सकता, सामाजिक अशांती से लगाया जा सकता, बेरोजगारी से नापा जा सकता, किसानों, नौजवानो, छात्रों की आत्महत्याओं से नापा जा सकता और एक प्रतिशत धनवानों के संपत्ती मे हो रहे बढौतरी के व्दारा समझा जा सकता है। जिस तरह से चुनावों का खेल खेला जा रहा है उससे यह उम्मीद नही कि जा सकती है कि कोई सरकार बदलकर जनता के पक्षधर अर्थनीति लाया जाय। जनअर्थनीति क्रांति के व्दारा इस व्यवस्था को जड से उखाड़कर ही बनाई जा सकती है। हर हाथ को काम, आवश्यकता के अनुसार दाम और आवश्यकता के अनुसार ही काम तब

ही संभव है जब व्यवस्था समाजवादी हो। साम्राज्यवाद के छत्रछाया मे हमने 70 साल गुजार दिए है, यह दलाल पूँजीवाद की व्यवस्था भारत की जनता को बेहत्तर जिंदगी देने मे नाकाम रही। भूख, बदहाली, अशांती, बिमारी, अशिक्षा, जलालत, जी हुजुरी, लाचारी के दिर्घ दौर ने जनमानस को कमजोर कर रखा है, उसे हिम्मत के साथ उठ खड़ा होना है, कमजोर मानसिकता से परे साहसी मानसिकता के लोंगों को संगठित होना है, ऐसी संगठित शक्ति चाहे छोटीही क्यों न हो यदी वह दृढ़संकल्पित होकर लक्ष्य की ओर बढ़ती रहती है तो कल व्यापक जनता उसके नेतृत्व मे निश्चित ही गोलबंद हो जायेगी और क्रांति सफल करते हुए भारत के सर्वांगिन विकास की जनअर्थनीति लायेगी जिसमे अरबों रुपयों की संपत्ती जमाकर रखने वाले जमाखोर गायब हो जायेंगे, लुट और शोषण खत्म होकर जनता का जीवनमान इतना उँचा उठेगा कि भारत का नागरिक ज्ञान, विज्ञान, कला और इन्सानियत मे दुनिया का सबसे बेहतरिन इन्सान होगा।

महाराष्ट्र सरकार 33 करोड़ ही पेड़ क्यों लगा रही?

महाराष्ट्र सरकार 33 करोड़ ही पेड़ क्यों लगा रही? 34 क्यों नही या 32 क्यों नही? क्यों कि ब्राम्हणों के देवता 33 करोड़ है। नव पेशवाई पर्यावरण का भी ब्राम्हणीकरण कर रही है। गौरतलब है कि इससे पहले 13 करोड पेड़ लगाने का दावा सरकार कर चुकि है पर उन्ही सालों मे महाराष्ट्र से वन क्षेत्र घटने के रिपोर्टस् है। पेड़ लगाने के समय बहुत ड़िगे हांकि जाती है, जैसे 'जलयुक्त शिवार' के लिए भी हांकि गई थी और 2019 के धुँपकाल ने इसकी पोल खोल दी, सैकड़ों गाव पिने के पानी के लिए तरस रहे है। लगाए गए पेड़ों का भी हाल यही है, कितने जिते है? 2015 मे राज्य मे 2 लाख52 हजार 928 चौ. किमी. जंगल था वह 2017 मे 2 लाख 52 हजार 871 चौ. किमी. रह गया है। यह 17 प्रतिशत कम हुआ है। दरअसल पेड़ जमीन से ज्यादा कागज पर लगाए जाते है, हर पेड़ के पिछे जो सरकारी खजाना खर्च होता है, वह है इस तथाकथित हरियाली का रहस्य।

किसान कोहराम

आमदानी दुगनी करने वालों को खैरात क्यों बाँटना पड़ रहा?

प्रधानमंत्री किसान आत्मसम्मान योजना यह मुख्य आर्थिक और औद्योगिक नीति का डॅमेज कन्ट्रोल है।

मोदी सरकार के पिछले पाँच साल किसानों के लिए किसी आपदा से कम नही थे। यह आपदा मोदी की वादा खिलाफी और किसान विरोधी नीतियों के कारण आई। मोदी को तो इसका कोई फर्क नही पड़ा वह वापस फिर पाँच साल के लिए गद्दी पर बैठ गए है। पर मोदी राज मे किसानों के बदहाली की दास्तान कोई भी सजग नागरिक भूल नही सकतें। 2014 के लोक सभा चुनावों में मोदी ने किसानों के लिए तीन मुख्य वादे किये थे। 1. स्वाामिनाथन आयोग रिपोर्ट का अमल. 2. 2022 तक किसानों की आय दोगुणी करना. 3. व्यापक कृषि बीमा योजना। चुनाव में किसानों से किए वादों से महज एक साल पूरे होने के पहले ही मोदी पलट गए। 20 फरवरी 2015 को मोदी सरकार ने तो बाकायदा सुप्रिम कोर्ट में हलफनामा दायर करते हुए कहा कि वह स्वामिनाथन आयोग की शिफारसों को लागू नहीं कर सकती इससे मार्केट में भारी उथल–पुथल मचेगी। फिर किसान आंदोलन का जोर देखकर और 2019 के लोकसभा चुनाव को देखकर 2018 के बजट में किसानों को डेढ़ गुना एमएसपी देने की बात और एक बार कही जो सरासर झूठ बात साबित हुई थी। किसानों की आय को दो गुणा करने का दूसरा वादा भी धोखा है यह बार–बार साबित हो रहा है। तीसरे कृषि बीमा योजना बीमा कंपनियों को मुनाफे पहुंचाने की योजना मे तब्दील कर दिया है।

मोदी सरकार ने अर्ध सामंती बुनियादी पर ही पिछले सरकारों के तरह

ही कार्य किया। वह अमेरीकी साम्राज्यवादियों के निर्देशन के अनुसार कृषि को कार्पोरेट कृषि के रूप में बदलने की योजना को तेजी से अमल किया। कॉन्ट्रक्ट फार्मिंग, कार्पोरेट फार्मिंग, ग्रुप फार्मिंग यह सब अंततः खेती को उद्योगपतियों के हाथों में सौंप कर किसानों को जमीन से बेदखल कर उन जमीनों में उन्हें मजदूर बनाने की नीति के बजाय और कुछ नहीं है। कृषि क्षेत्र और किसानों को शोषण कर देश–विदेश कार्पोरेट घरानों के लिए सुपर मुनाफे पहुंचाना ही मोदी सरकार का मूलमंत्र है। इसके लिए किसानों के विकास के नाम पर मंत्रालय का नाम बदलना जैसे नाटक बहुत किए जा रहे हैं। मीठी–मीठी शब्दों के आवरण में किसान विरोधी नीतियाँ ही लायी जा रही है। दुनिया भर के व्यापार के एकाधिकार के जरीये खेती, उद्योग पर कब्जा जमाये हुए मेनसेंटो, वॉलमार्ट जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए भारत में दरवाजे खोल दिए हैं और उसके सुविधा के अनुरूप कृषि नीतियाँ बनाई जा रही है। राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद की एक बात को मोदी की कृषि नीतियों से जोड़कर गौर करना है, जिसमें कहा है कि 2022 तक खेती पर निर्भर 58 प्रतिशत जनसंख्या को 38 प्रतिशत तक लाना है। इसका सीधा मतलब कुछ को मार डालना, कुछ को दिहाड़ी मजदूर बनाना। इस नीतियों वजह से ही उल्लेखनीय संख्या में किसान आत्महत्या करने के साथ–साथ खेतीबाड़ी छोड़कर 70 प्रतिशत किसान शहर जाने की इच्छा जाहीर किये हैं। हर दिन 100 किसान किसानी छोड़ देते है।

मोदी ने किसानों के लिए 10 सूत्री कार्यक्रम : 1. आय दोगुणी करना, 2. फसल बीमा योजना, 3. कृषि सिंचाई योजना, 4. मृदा स्वास्थ कार्ड, 5. जैविक खेती, 6. दलहन और तिलहन मे आत्मनिर्भरता, 7. नीम लेपित युरिया, 8. राष्ट्रीय कृषि बाजार, 9. मोबाईल एप, 10. प्रकृति आपदा राहत।

मोदी शासन के पाँच साल का क्रियान्वयन देखने से किसानों का एक भी कार्यक्रम धरातल पर खरा नहीं उतरा है। यह मात्र राजनीतिक रूप से फायदे के लिए मीडिया के सुर्खियों में लफ्फाजी के साथ लाया गया कार्यक्रम है। 2022 तक आय दोगुणी करना : 17 राज्यों के आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में कहा है कि किसानों की सालाना आय 20,000 रूपये है। यह प्रति माह 1,662 रूपये

होती है। 2022 तक आय को दोगुणी करने की बात कही जा रही है तो यह 3,332 रूपये प्रति माह हो जायेगी। यदी मुद्रास्फिती को शामिल कर लिया जाय तो यह होनेवाली दोगुणी आय कोई हैसियत नहीं रखती। वैसे भी यदी 2022 तक किसानों की आय दोगुणी भी करनी हो तो कृषि का विकास दर 14 प्रतिशत चाहिए जो आज मात्र 2 प्रतिशत है।

मोदी की आय दोगुणी करने की बात भी कैसी झूठी है यह भी देख सकते हैं। 2017–18 में देश का जीडीपी 6.2 प्रतिशत है। कृषि जीडीपी 4.9 से खिसककर 2.1 प्रतिशत पर आ गया है (2014 से 2018 के बीच औसतन 1.9 प्रतिशत)। मोदी के शासनकाल में कृषि ग्रास वेल्यू एडेड (जीवीए–सकल मूल्यवर्धन) 5 प्रतिशत से भी कम रही। वर्ष 2016 के तीमाही में यह तीन बार ऋणात्मक रही जिसमें 3.05 प्रतिशत की गिरावट रही। फसलों की उपज रीकॉर्ड स्तर पर होने के बावजूद कीमतों में आई गिरावट के कारण किसानों की शुद्ध आय को कम कर दिया। (टर्म्स ऑफ ट्रेड) व्यापार के शर्तें लगातार कृषि क्षेत्र के प्रतिकुल बना रहा। कृषि में सकल पूंजी निर्माण में गिरावट चल रही है, यह 2014–15 मे 8.3 प्रतिशत था वह 2015–16 में 7.8 प्रतिशत हो गया। बारिश की कमी के कारण 20 से 25 प्रतिशत आय कम हो रहा है। इस तरह किसानों की आय दोगुणी करनी है तो वर्ष 2018 को आधार मानेंगे तो 14 साल लग जायेंगे। और इन 14 सालों में बढ़ने वाली खेती में पूंजी का महंगाई और रूपये का जो अवमूल्यन होगा वह जोड़कर सोचा जाय तो दोगुणी होनेवाली आय दरअसल मूल्य के हिसाब से आधी भी नहीं रह जायेगी। अतः आय दोगुणी होने से भी किसानों के जीवन में कोई बदलाव नहीं आनेवाला और तो और ऋणभार से, भूखमरी और बढ़ती बीज, खाद आदि के महंगाई की समस्या से वह आय किसानों को बदहाली से बाहर नहीं लाने वाली है और ना ही गंभीर होते जा रहे कृषि संकट को सुलझानेवाली है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) : केन्द्र सरकार किसानों के उत्पादन को न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है। एक तो यह लागत के तुलना में नहीं है, वास्तविक लागत खर्च के एक तिहाई के आसपास ही न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है। **पहली** बात तो यह है कि, यह किसानों की आर्थिक वृद्धि के लिए

नहीं बल्कि वास्तविक कृषि उपज के दाम नियंत्रित करने का काम करता है। जिस तरह से समर्थन मूल्य तय किए जा रहे हैं, वह देखने से एमएसपी यह संकल्पना ही किसानों के साथ एक धोका है। **दूसरा**, भारत सरकार ने 23 फसलों का एमएसपी घोषित किया उसमें से केवल 3–4 फसलों को ही सीमित मात्रा में खरीदती है। एमएसपी के आधार पर किसान की मजदूरी सालभर में विभाजित करे तो वह केवल 20 से 30 रूपये प्रतिदिन होती है। **तीसरा,** किसानों पर आधार पंजीकरण, टोकन लेना वगैरे बहुतसी शर्तें लगाए हैं। **चौथा,** किसानो से खरीदा गया उत्पादनों का भुगतान वक्त पर नहीं दिया जा रहा है। इससे मजबूरन किसान कम दाम पर साहूकारों को अपना उत्पाद बेचने में मजबूर है। तब किसान की आय दोगुणा होना तो दूर उल्टा बची खुची आय गवाँ बैठने की नौबत आ गई है।

जब तक किसानों के उत्पाद को पूरी तरह खरेदी करने की गारंटी नहीं होती तब तक एमएसपी ज्यादा रखने से भी किसानों को कोई फायदा होनेवाला नहीं।

कर्ज माफी : देश में कुल 4,68,48,100 किसान कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं। उन पर 30 दिसंबर 2016 तक 12.60 लाख करोड़ रूपयों का कुल कृषि कर्ज है। देश का प्रत्येक किसान औसतन 47,000 रूपये का ऋणी है। किसानों के कर्ज पर बैंक द्वारा लिया जानेवाला ब्याज 42 प्रतिशत है। मूल कर्ज पर ब्याज दर 17.50 प्रतिशत, कर्ज नहीं चुकाया तो कर्ज और ब्याज को मिलाकर फिर 17.50 प्रतिशत ब्याज, 3 प्रतिशत दंड, 3.5 प्रतिशत सरचार्ज और 2 प्रतिशत वसूली का खर्च – इस तरह 42 प्रतिशत ब्याज किसानों से आंका जाता है। किसान अपने लिए गए कर्ज से दोगुणा से भी ज्यादा वापस देता है फिर भी वह कर्ज से कभी मुक्त नहीं होता। लिहाजा किसानों की आत्महत्या जारी है।

सरकार ने कंपनियों की 45,17,466 करोड़ रूपये की कर माफी 2005–06 से 2014–15 में की। यानी हर साल लगभग 4.5 लाख करोड़ रूपयों की माफी कंपनियों को दी जा रही है। पर किसानों को कर्ज माफी नहीं दी है। यह जीता जागता ताजा सबूत है कि मोदी सरकार साम्राज्यवादियों, बड़े सामंतियों

और बड़े पूंजीपतियों की सरकार है एवं किसान विरोधी है।
जो कृषि ऋण के लिए 10 लाख करोड़ रूपये बजट प्रावधान है। उसमें किसान और कृषि कार्पोरेट कंपनियों के लिए अलग–अलग रूप से आवंटन नहीं है। अतः आज तक के ऋण बटवारें को प्रतिशत के रूप में देखने से यह स्पष्ट है की 10 लाख करोड़ रूपये में से 8 लाख करोड़ रूपये तक का कर्ज किसानों के बजाय कृषि कार्पोरेट कंपनियाँ ले जायेगी। कृषि क्षेत्र के लिए फंड के परिमाण (कर्ज आपूर्ति वगैरे) लगातार बढ़ते रहे हैं। 2004 में 96,000 करोड़ रूपये थे वह अब 10 लाख करोड़ रूपये हुए। पर 50 प्रतिशत से भी ज्यादा फंड शहरी ब्रँचेस द्वारा फुड प्रोसेसिंग, फुड पार्क वगैरे में जाता है। कृषि के नाम पर दिया जा रहा कर्ज दरअसल कार्पोरेट कंपनियों और बड़े किसानों को जाता है। 1990 में 2 लाख रूपये से भी कम कर्ज लेनेवाले 92 प्रतिशत थे। वह आज 2018 में 46 प्रतिशत रह गए। इसका अर्थ कृषि के लिए ली जाने वाली कर्ज 54 प्रतिशत सीधे बड़ी रकम में जा रही है। इसका अर्थ होता है कि जरूरतमंद किसानों का हिस्सा दिन ब दिन लूटा जा रहा है। 44 प्रतिशत कर्ज गैर–संस्थाओं से (साहुकारों से) लिया जा रहा है। ऐसे में कर्ज माफी से केवल 56 प्रतिशत की ही बात होती है, दरअसल कर्ज माफी किसानों से ज्यादा बैंको को फायदेमंद साबित हो रही है।

पिछले तीन सालों में कार्पोरेट जगत को 17.5 लाख करोड़ रूपये का फायदा मिला। लेकिन उन्होंने 6.8 लाख करोड़ रूपये का कर्ज डुबाया है। 44 प्रतिशत कृषि ऋण वाणिज्यिक बैंकों की शहरी शाखा से बाटें गए। वर्ष 2005 से 2013 के दौरान छोटे और सिमांत किसानों को मिलने वाले 25 हजार रूपये तक के प्रत्यक्ष कृषि कर्ज की हिस्सेदारी 23 प्रतिशत से घटकर 4.3 प्रतिशत रह गई है। वहीं 1 करोड़ रूपये से ज्यादा प्रत्यक्ष कृषि कर्ज की हिस्सेदारी 7.5 प्रतिशत से बढ़कर 10 प्रतिशत पहुंच गई है। आरबीआई के आकडों के मुताबीक वर्ष 2015–16 में कृषि क्षेत्र का 7.4 प्रतिशत कर्ज दबाव में है। यानी जिन्हें लौटाना मुश्किल हो रहा है। वहीं औद्योगिक क्षेत्र में यह 19.4 प्रतिशत है। आरबीआई रिपोर्ट मार्च 2016 बताती है कि 6 प्रतिशत कृषि कर्ज डिफाल्ट हुआ जबकि कंपनियों ने 14 प्रतिशत कर्जों में डिफाल्ट किया। सरकारी आकड़े

खुद बता रहे हैं कि किसान से ज्यादा डिफाल्टर पूंजीपति है। पर कोई पूंजीपति आत्महत्या नहीं करता, क्योंकि सरकार हर साल उन्हें कर्ज माफी और टैक्स माफी देते रहते है।

किसानों के कर्ज माफी पर सरकार की दोगली नीति है। राजनीतिक नेता कर्जमाफी की घोषणा करते हैं और उनके अधिकारी उसके उल्टा बोलते हैं। कर्ज माफी पर रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल इसे नैतिक त्रासदी कहते थे। स्टेट बैंक की अध्यक्ष अरूंधती भट्टाचार्य इसे कर्ज अनुशासन बिगाड़ने वाला कदम बताती है, तो बैंक ऑफ अमेरिका के मैरिल लिंच इसका बैंको के बेलन्स शीट पर बुरा असर वाला कदम बताते हैं। तो सवाल खड़ा होता है कि क्या वाकई सरकार कर्जमाफी करने जा रही है या यह महज जुमले बाजी है?

किसानों के आंदोलनो के सामने झुककर कुछ राज्यों ने कर्जमाफी की घोषणा की है पर उसपर सही अमल अब तक नहीं किया है। कर्जमाफी किसानों से ज्यादा बैंको को राहत साबित हो रही है। कर्जमाफी की बात होती है पर वास्तव में पूरी कर्जमाफी कभी नहीं की है। कई शोध और आंकड़ों द्वारा पता चलता है कि किसान किसानी करने के लिए लीए जाने वाले कर्जों में सिर्फ 31 प्रतिशत ही बैंकों से उपलब्ध है बाकी 69 प्रतिशत निजी कर्जों पर निर्भर है। यानी, बैंको से लिया पूरा कर्ज माफ कर भी दिया जाय तब भी किसान कर्ज से मुक्त नही होगा इसीलिए कर्जमाफी देने के बावजूद किसानों की आत्महत्याएं जारी है।

फसल बीमा योजना : प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पूर्व की तीन बीमा योजना एनएआईसी, एमएनएआईएस, डब्लूबीसीआईएस इनको मिलाकर बनाई गई। इस योजना में 2016 में बीमा कंपनियो ने 10,000 करोड़ रूपये का मुनाफा कमाया। वहीं किसानों ने जो 6,000 करोड़ रूपयों का दावा किया था। उनमे से केवल 2,000 करोड़ रूपये ही किसानों को मिला है। कैग (सीएजी–कन्ट्रोलर ऑडिटर जनरल) की रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रीमियम सब्सिड़ी के तौर पर 10 निजी बीमा कंपनियों को सरकारी क्षेत्र की एग्रीकल्चरल बीमा कंपनी ने दावों का वेरिफिकेशन किए बगैर ही 3,622.79 करोड़ रूपये का

भुगतान कर दिया। इससे बिल्कुल साफ हो गया है कि फसल बीमा योजना किसानों के लिए नहीं बल्कि बीमा कंपनीयों के लिए है जो दलाल नौकरशाह पूंजीपतियों की है।

बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) के मुताबिक गैर–जीवन बीमा कंपनियों की आय 2015 की तुलना में 25 प्रतिशत बढ़ गई है। कुल प्रीमियम आय (डायरेक्ट प्रीमियम इनकम अंडर रिटेन) बढ़कर 9,760.23 करोड़ हो गई। यह दिसंबर 2015 की 777.38 करोड़ रूपये के तुलना में 25 प्रतिशत अधिक है। निजी क्षेत्र की बीमा कंपनी की आय दिसंबर 2016 में 4,775.35 करोड़ रूपये थी। यह बढ़ोतरी दूसरा–तीसरा कुछ नहीं बल्कि किसानों के खून पसीने की लूट है। फसल का नुकसान 50 प्रतिशत से कम रहने से बीमा नहीं देते। 2016–17 में फसल बीमा योजना में 20,478 करोड़ रूपये सरकार ने बीमा कंपनियों को प्रीमियम यानी बीमा के तौर पर दिए। कंपनियों ने 5,650 करोड़ रूपये किसानों को बीमा के रूप में दिए और 14,828 करोड़ रूपये कंपनियों ने हड़प लिए।

कृषि सिंचाई : देश की 16.2 करोड़ हेक्टर कृषि क्षेत्र में से केवल 4.5 करोड़ हेक्टर जमीन को ही सिंचन की व्यवस्था उपलब्ध है। तमाम पूरे और आधे अधुरे स्रोतों को भी जोड़ने से 34.5 प्रतिशत से ज्यादा सिंचन नहीं है। बड़े बांध जिसका निर्माण सिंचाई के नाम से किया गया उसका पानी सिंचाई के बजाय कार्पोरेट कम्पनियों और कारखानों दिया जाता है। वर्ष 2018 में सरकार ने कृषि सिंचाई योजना पर 2,600 करोड़ रूपया खर्च करने की बात कही थी, लेकिन देशभर में जो अधुरी पड़ी सिंचाई योजना है उसे ही पूरा करने मे चार लाख करोड़ रूपयों की जरूरत है। सिंचाई की परियोजनाओं को घोषणा करना, उसके लिए बजट अलाट करना, फिर वह पैसा गबन करना यह हर सरकार करते आया है। 'जलयुक्त शिवार' यह महाराष्ट्र की योजना बहुत जोर शोर से शुरु की गई पर महाराष्ट्र सिंचन की बात तो दुर पीने के पानी के लिए तरस रहा है।

पिछले पाँच साल के भूक्तभोगी भारत के किसान क्या उम्मीद कर सकते है मोदी की दुसरी पारी से? मोदी का पाखंड सरचढ़कर बोल रहा है।

किसानों की आमदानी दोगुनी करने वालों को खैरात क्यों बाँटनी पड़ रही है? प्रधानमंत्री किसान आत्मसम्मान योजना खुद्दार किसानों को लाचार बनाने की योजना है। धरती का सिना चिरकर अनाज उगानेवाला किसान, न केवल अपना पेट बल्कि औरों की भूख मिटाने वाला अन्नदाता को इतना मजबूर और दया का पात्र बना दिया है कि उसे अपमानजनक आत्मसम्मान नाम की सरकारी योजना के टुकडों पर जीना पड़ रहा है। यह संकेत है कि देशभर मे किसान इतनी बुरी हालत मे है कि उन्हे जिंदा रखने के लिए उनके खातों मे पैसे डालना पड़ रहा है। यह सरकार की नीतियों का परिणाम है और आत्मसम्मान योजना इन्ही नीतियों से जो डॅमेज (बर्बादी) हो रहा है उसे कन्ट्रोल करने के लिए लाई गई है। किसानो की बर्बादी का कारण नैसर्गिक या दैवीक नही है यह राजनीतिक है। भारत का मौजुद राजनीतिक ढ़ाँचा किसानों की समस्या का समाधान नही कर सकता। जो किसानो के हित का नही है उसे ध्वस्त करना जरुरी है। किसान तो सैकड़ो संगठनो मे संगठित है पर क्या कोई संगठन किसानों की समस्या का हल बता रहा है? क्या केवल कर्जमाफी के आंदोलनो से यह समस्या हल होगी? जबतक किसान गुमराह रहेंगे तबतक मौतों की गिनती बढ़ती रहेगी। किसानों को मोदी के पिछले पाँच साल और हाल मे हुए चुनावों से समज लेना चाहिए कि किसी राजनीतिक पार्टी को किसानों की पर्वा नही है। कृषि क्रांति ही इसका उत्तर है। किसान संगठनों को अपना कार्यक्रम कृषि क्रांति के तहत करना जरुरी है। देशभर मे जारी नवजनवादी क्रांति के जनयुध्द मे किसानों की हिस्सेदारी ही उन्हे उनके बर्बादी से बाहर निकालेगी। ✶

सच्चे जनवादी भारत के निर्माण के लिए, ब्राम्हणी हिन्दू फासीवाद के खिलाफ लड़ना, हर आजादी पसंद लोगों का कर्तव्य है!

बलिदान की गाथा

जनता की लाडली जननेत्री कॉमरेड जमुना अमर रहे!

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की जुझारु जननेत्री कॉमरेड जमुना (सगुना, सागेन) उर्फ लिलाबाई मरकाम दुश्मनों के एक हमले मे 19 मार्च 2019 को तांडा क्षेत्र के जंगल मे शहीद हुई। कॉ. जमुना को भाकपा(माओवादी) महाराष्ट्र–मध्यप्रदेश–छत्तीसगढ़ स्पेशल जोनल कमेटी (एमएमसी) अपनी भावभिनी आदरांजली अर्पित करती है।

बालाघाट जिले के बैहर तहसील के माटे गांव के मध्यम वर्गिय आदिवासी मरकाम परिवार मे जमुना का जन्म हुआ। माता रजलीबाई और पिता गेंदू मरकाम के सात बच्चों मे जमुना छटवी संतान है। साम्राज्यवादी और सामंती शोषण तथा रितीरिवाज और पितृसत्ता के बोझ तले महिलाओं की जिंदगी दबी है, यह भारत के हर क्षेत्र और हर समाज की स्थिती है, आदिवासी समाज भी इससे अछुता नही है। बाल विवाह की पंरपरा महिलाओं की गुलामी की एक जंजीर है। इस जंजीर मे जमुना को भी बाँध दिया गया था। इसी तरह की कई सामंती जंजीरो से मुक्त होने की छटपटाहट युवा लिलाबाई मे थी, उसे आवश्यकता थी हिम्मत की, सही रास्ते की, सही मंजील की वह उसे माओवादी पार्टी मे मिली। बालाघाट जिले के ग्रामिण आंचल मे जनमुक्ति के लिए दिर्घकालिन जनयुध्द का बिगुल माओवादी पार्टी ने जब फुंका तो यहाँ की जनता हिम्मत महसुस करने लगी और संगठित होने लगी। पार्टी के विचारों से प्रभावित होकर जमुना भी जनता के साथ पार्टी कार्यो मे भाग लेने लगी।

वह मिटींगो को ध्यान से सुनती थी और युवक–युवतीयों मे तथा आम जनता मे जाकर पार्टी के विचार बताती थी। युवकों को इकट्ठा करके पोस्टर चस्पाना, बॅनर बाँधना जनता मे पर्चे वितरीत करना और छोटी सभाएँ लेकर प्रचार करना इस तरह वह कार्य को निभाती थी। 1992 से 1996 तक प्रचार दल की जिम्मेदारी निभाने के बाद नियमित दल मे 1996 मे शामिल हुई। उस वक्त भारत बंद के दौरान लौंगुर घाटी मे हुई प्रतिरोध कार्रवाई मे भी शामिल हुई। महिला विरोधी सामाजिक रिती रिवाज ने जमुना के मन मे बचपन मे ही चीढ़ निर्माण की थी। पार्टी मे शामिल होने के बाद वह चिढ़ क्रांतिकारी संघर्ष की राजनीतिक चेतना मे बदल गई। पार्टी मे आने के बाद बहुत जल्द ही पढ़ना–लिखना सिख गई। पितृसत्ता और महिला विरोधी विचारों के खिलाफ वह बहुत सजग थी और ऐसे विचारों के खिलाफ ड़टकर संघर्ष करती थी। उसने प्रथम बालाघाट जिले के परसवाडा दल, मलाजखंड दल और फिर तांडा दल मे सदस्य के रुप मे कार्य किया। पार्टी के आदेश पर उसने बालाघाट, राजनांदगाँव, गोंदिया और गडचिरोली जिले मे भी जाकर अपना योगदान दिया। गाँव मे रहते समय से ही जनभिमुख और सामाजिक स्वभाव के कारण वह जल्दी ही जनता मे घुलमिलकर कार्य करने वाली एक अच्छी क्रांतिकारी कार्यकर्ता बन गई। 2004 मे वह एरिया कमेटी की सदस्य बनी मलाजखंड मे कुछ समय भूमिका निभाने के बाद उसने तांडा एरिया मे जिम्मेदारी संभाली। यहाँ पर जनता मे इसतरह घुलमिल गई की जनता उसे यहीं की अपनी बेटी समजते थे। यहाँ की जनता को संगठित करने मे उसकी बड़ी भूमिका है। उसने क्रांतिकारी महिला संगठन को तांडा एरिया मे बहुत मजबूती प्रदान की। महिलाओं मे क्रांतिकारी चेतना का संचार होने के कारण महिला दिन मनाने ने से लेकर विभिन्न क्रांतिकारी कार्यक्रमो, आंदोलनों मे उनकी गोलबंदी अच्छी खासी रहती थी। उनके संगठन कौशल और संयमी स्वभाव के कारण जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं के दिलों मे सबकी दिदी के रुप मे सम्मानित स्थान प्राप्त कर चुकी थी। वह केवल तांडा एरिया सचिव ही नही बनी बल्कि, निर्विवाद रुप से तांडा एरिया की जननेता थी। टांडा क्षेत्र मे जनचेतना और जनयुध्द का विकास करते हुए जनसत्ता का भृण रुप क्रांतिकारी जन कमेटीयाँ

बनाई गई थी। इन कमेटीयों के व्दारा तालाब निर्माण से लेकर अन्य आर्थिक विकास के कार्य हाथ मे लिए गए थे। जनता स्वयं अपना विकास करने के लिए कॉ. जमुना के नेतृत्व मे आगे बढ़ रही थी। गांवों मे जनडॉक्टरों का निर्माण भी चालु किया था। जनता की स्वयं विकास की पहल देखकर सरकार के कान खड़े हुए और वे जनता के इस विकास कार्य पर हमला करने लगे। कॉ. जमुना को लक्ष्य बनाकर पुलिस ने कई बार हमले किए। हर हमलों का पीएलजीए ने जनता के साथ मिलकर करारा जवाब दिया। जमुना जनता को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक के साथ–साथ सांस्कृतिक विषयों पर भी सचेत करती थी। आदिवासी संस्कृतिपर ब्राम्हणी हिन्दू फासीवाद के हमले के विरोध मे आदिवासी अस्मिता बचाने के लिए न केवल संगठन को निर्माण किया बल्कि हिन्दू धर्म की घुसपैठ के खिलाफ जनगोलबंदी करते हुए आदिवासी संस्कृति की रक्षा की। तेंदू पत्ता की रोजी बढ़ाने, बांस कटाई की रोजी बढ़ाने के लिए हर साल जनसंघर्ष को जमुना ने मार्गदर्शन किया। जंगल संपदा के साथ–साथ टांडा क्षेत्र मे खनिज संपदा भी भरपूर है। टुडागढ़ और बसंतपूर मे खदान खोलने के लिए सरकार ने कोशिशे की, जमुना के नेतृत्व मे जनता ने लगातार प्रतिरोध किया जिससे अभीतक टांडा क्षेत्र की जनता विस्थापित होने से बच पाई है। महिलाओं के विकास पर ध्यान देने के लिए पार्टी ने जब डिवीजन स्तर की महिला सब कमेटी बनाई थी, जमुना तब उस कमेटी की महत्वपुर्ण सदस्य बनी थी। एक साधारण सदस्य से लेकर डिवीजन स्तर के नेतृत्व तक अपना क्रांतिकारी सफर पुरा करने तक कितने भी उतार–चढ़ाव आए, कठिण परिस्थितीयाँ आई पर वह कभी विचलित नही हुई। पार्टी दिशा और सिध्दान्त के उपर उसका दृढ़ विश्वास था। वह बिना किसी चमक–धमक और दिखावे अपने लक्ष्य के तरफ आगे बढ़ती रही और भारत के क्रांतिकारी इतिहास मे अपना अनमोल योगदान दर्ज किया। सांगठनिक कौशल के साथ ही सैनिकी कार्रवाईयों मे भी जमुना का योगदान भूला नही जा सकता। नारंगी ऑम्बुश और ऐसे बिसीयों सैनिकी कार्रवाईयों मे भाग लेकर एक बहाद्दुर योध्दा का उसने परिचय दिया। 18 जनवरी 2019 को जब तांडा मे दुश्मनों ने डेरा पर हमला किया तब भी जमुना ने अपने कार्बाईन से दुश्मनों पर जवाबी

फायरिंग करते हुए दुश्मनों को आगे बढ़ने से रोककर रखा था। जमुना का जनमान्य नेतृत्व सरकार और खनिज संपदा लुटने वाले साम्राज्यवादी और दलाल नौकरशहा पूंजीपतियों के कंपनियों को रास्ते का कांटा लग रहा था इसलिए जमुना को खत्म करने की कई दिनों से पुलिस की कोशिशें जारी थी। गद्दार पहाडसिंग ने टांडा मे पार्टी की गतिविधियों की जानकारी दुश्मनों को देने के बाद टांडा मे पुलिस के कई कैंम्प डाले गए, जनता मे नेतृत्व करने वाले, संगठन के कार्यकर्ता और गुरिल्ला गतिविधियों की जानकारी दुश्मन को मिलने के कारण दमन और गहरा किया गया और जमुना को लक्ष्य बनाकर कई संयुक्त दमन अभियान चलाए। ऐसे ही 19 मार्च 2019 के हमले मे जमुना विरगति को प्राप्त हुई।

जमुना एक शालिन, शांत, संयमी, बहादुर और दृढसंकल्पित जननेत्री थी। उसे जनता के दिलों से दुनिया की कोई ताकत जुदा नही कर सकती। उसके कार्य, उसके विचार जनता कभी नही भूल सकती। भाजपा के प्रध ाानमंत्री नरेन्द्र मोदी और काँगेसी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भाडोत्री हमलावरों जमुना को नही मारा है, जनता के कलेजे को चिरा है, जनता यह घाव कभी सहन नही करेगी। जनता जमुना ने बताए मार्ग पर चलते रहेगी। जमुना ने बनाए संगठन, जमुना ने जनता के मन–मस्तिष्क मे भरी क्रांतिकारी चेतना क्रांति की भौतिक शक्ति बनकर अपने लक्ष्य के तरफ आगेकुच करती रहेगी। जनता की प्यारी बेटी, चहेती जननेत्री को मारकर, जनता के दिलों मे घाव देकर, डरा धमकाकर दुश्मन सोच रहे होंगे के वह क्रांति को रोक देंगे पर यह उनके मनसुबे कभी कामयाब नही होंगे।

हम लड़ेंगे और मजबूती के साथ जमुना के सपनों को साकार करने, जुल्मी शाशकों के राज से मुक्ति करने, ब्राम्हणी हिंदू फासीवादीयों से भारत को मुक्त कर सच्चा जनवादी भारत निर्माण करने जनता की यह लड़ाई जारी रहेगी। प्यारी जनता को पार्टी का आवाह्न है कि, जमुना के सपनों को साकार करने के लिए उसके बताए रास्ते पर दृढता से आगे बढ़े। दुश्मनों का दमन, डराना, धमकाना, फुसलाना, गद्दारी के लिए उकसाना इन सारे हथखंडों के खिलाफ दृढतापुर्वक प्रतिरोध करने आगे बढ़े। तकलिफें, कठिनाईयाँ, त्याग

और बलिदान क्रांतिकारी जनयुध्द मे कोई नई बात नही है। बिरसा मुंडा, गुंडाध ुर, भगतसिंह से लेकर जमुना तक यह परंपरा जारी है और आगे भी विर योध दाओं के खुन से सिंचकर ही क्रांति आगे बढ़ेगी। जनयुध्द को रोकना किसी ताकद के बस की बात नही। दुश्मन वर्ग जितना चाहे जोर अजमाए अंतिम जित जनता की ही होगी। इसलिए जमुना के बलिदान की कहानी हर घर मे हर नौजवान और बुढ़े बच्चों मे लेकर जाओं और जमुना की जगह लेने के लिए नये नौजवान क्रांतिकारी बनकर आगे बढ़ो। जमुना को आदरांजली देने गाँव–गाँव मे संस्मरण सभा आयोजित करों। दुश्मनों ने नये सिरे से जारी किए समाधान नाम के दमन योजना को हराने तमाम जनता प्रतिरोध संघर्ष को तेज करों।

कॉमरेड रामको को लाल सलाम!

भारत के नवजनवादी क्रांति के वेदी पर 27 अप्रैल 2019 को गडचिरोली जिले के कोठी पुलिस कैम्प के अंतर्गत कंजुरवाही के जंगल मे महाराष्ट्र पुलिस व्दारा कॉमरेड रामको डिवीजनल कमेटी सदस्य एवं कॉमरेड शिल्पा की हत्या की है। इसका हम खंडन करते है। जनता की प्रिय जननेत्री रामको की शहादत व्यर्थ नही जायेगी। गडचिरोली जिले मे उन्होने जनता जगाई क्रांति की चेतना संगठित शक्ति के रुप मे आगे अपने लक्ष्य के तरफ बढ़ती रहेगी। कॉ. रामको जनसंघर्ष मे जनयोध्दाओं की प्रेरणा बनकर हमेशा अमर रहेगी। शहीद कॉ. रामको और शिल्पा अमर रहे। कॉ. रामको और शिल्पा के सपनों को पुरा करने आगे बढ़ेंगे। दुश्मन वर्ग को इनके हत्या की किमत चुकानी पडेगी।

(28 जुलै से 3 अगस्त..... पेज नंबर 44 से) प्रकृति और मानवी समाज के सामने अस्तित्व का संकट निर्माण करने वालों के खिलाफ है। यह जनता के दुश्मन है। इनका वर्ग संख्या मे नगन्य है पर उन्होने राजनीतिक सत्ता पर कब्जा जमाकर रखा है और इसके ताकद के बलपर उन्होने विशाल जनता के जीवन यापन को कन्ट्रोल करके रखा है।

जबतक जनता यह राजनीतिक सत्ता इन लुटेरे वर्ग के हाथ से नही छिनती तबतक न तो समाज मे शांती स्थापित होगी और न प्रकृति को बेरोकटोक दोहन रुकेगा। इसलिए भारत की कम्युनिस्ट पार्टी(माओवादी) ने देशभर मे इन लुटेरे वर्गो के खिलाफ जनयुध्द छेडा है। इस जनयुध्द मे जनता की सेना जनमुक्ति छापामार सेना (पीएलजीए) अगुवाई भुमिका निभा रही है। शोषित जनता के बेटे–बेटीयाँ इसमे शामिल होकर, अपने प्राण अर्पित करते हुए, अपने खुन को सिंचते हुए इस जनयुध्द को जारी रखे हुए है। देशभर की शोषित जनता अपने प्यारे बेटे–बेटीयों की शहादत पर हर साल 28 जुलै से 3 अगस्त तक शहीद सप्ताह मनाते है। गांवो से शहरों, खेत–खलिहानों से जंगलो तक जहाँ–तहाँ जनता इकट्ठा होते है, लाल झंडा फहराते है, शहीदों के सम्मान मे श्रध्दांजली अर्पित करते है, शहीदों के जीवन और कार्यो की चर्चा करते है, उनसे प्रेरणा लेकर जनयुध्द को और आगे ले जाने की कसम खाते है और इस लड़ाई को आगे ले जाने के लिए अपने बेटे–बेटीयों को पीएलजीए मे भर्ती करने भेजते है।

जनयुध्द जहाँ मजबूती से लड़ा जा रहा है वहाँ शहीद सप्ताह मनाना जनता की संस्कृति, परंपरा और जीवनधारा का अंग बन चुका है। जनयुध्द के विस्तार क्षेत्र की जनता से पार्टी आवाह्न करती है कि, आप भी लड़ाकू जनता की इस परंपरा का हिस्सा बनकर आगे बढ़े। पिछले एक साल मे देश भर मे दंडकारण्य, झारखंड, ओडिशा, आंध्रा, तेलंगना, महाराष्ट्र–मध्यप्रदेश–छत्तीसगढ़ झोन मे मिलाकर सैकडों जनयोध्दा विरगति को प्राप्त हुए है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के छुई खदान तहसिल के अंतर्गत तांडा एरिया मे कॉमरेड जमुना (लिलाबाई मरकाम), डीवीजनल स्तर की नेता दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हुई है। 1992 से पार्टी मे कार्यरत यह कॉमरेड एक बहादुर जननेत्री थी।

गडचिरोली जिले की जननेत्री कॉमरेड रामको भी दुश्मनों से लड़ते हुए विरगति प्राप्त हुई है। बस्तर मे कॉमरेड सुर्या जो जनयोध्दाओं के प्रशिक्षक थे दुश्मनों से आखरी सांस तक लड़ते हुए अपने साथ आठ योध्दाओं के साथ शहीद हुए है। गडचिरोली जिले मे टीपागड क्षेत्र मे कॉ. पंकज और कॉ. बबीता शहीद हुए है। कबीरधाम, मंडला जिले मे क्रांति का विस्तार करने आए जनयोध दा कॉ. सुनिल और कॉ. प्रतिमा दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हुए है। इस तरह देशभर मे सैकड़ो विर योध्दाओं ने जनता की मुक्ति के लिए अपने प्राण अर्पण किए है। उन तमाम शहीदों को भारत की कम्युनिस्ट पार्टी(माओवादी) अपनी भावभिनी आदरांजली अर्पित करती है। उनके अधुरे सपनों को साकार करने की कसम खाते है।

ब्राम्हणी हिन्दू फासीवादी भाजपा की केन्द्र की मोदी सरकार और राज्यों मे स्थित कॉंग्रेसी सरकारें यह सोच रहे है कि जनयोध्दाओं की हत्या करके क्रांति को खत्म कर देंगे पर यह उनके मनसुबे कभी कामयाब नही होंगे क्योंकि यह जनता का युध्द है, जनता के मुक्ति के लिए है और खुद जनता ही लड़ रही है, तथा जनता के बेटे–बेटीयाँ ही जनमुक्ति छापामार सेना मे भर्ती होकर लड़ रहे है। भारत की जनता 130 करोड है, कितनों को मारेंगे? उनकी बंदुके और गोलियाँ खत्म हो जायेंगी पर जनयोध्दा की कभी कमी नही होगी। एक शहीद होगा तो उसके जगह उनसे प्रेरणा लेकर हजारों आगे बढ़ेंगे। पिछले 45 सालों मे 14 हजार वीरों ने बलिदान दिया है और आगे भी देंगे पर यह जनयुध्द अंत मे अपने विजय की मंजील पर जाकर ही खत्म होगा। यह जनता की और प्रकृति की जरुरत है कि, भारत मे नवजनवादी क्रांति सफल करके ही हम अपने समाज, अपने देश और प्रकृति को संरक्षित कर सकते है। लुटेरे शाशकों को नेस्तनाबूत करके ही हम भारत मे सामाजिक शांति, समानता, सबको स्वातंत्र, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ और न्याय तथा भाईचारा स्थापित कर सकते है। इसलिए पार्टी जनता और खासकर नौजवानों को आवाह्न करती है कि जनयुध्द मे आगे बढ़े, पीएलजीए मे भर्ती होकर अपने महान कर्तव्य का पालन किजीए।, **नवजनवादी क्रांति जिंदाबाद!,**

महाराष्ट्र–मध्यप्रदेथ–छत्तीसगढ़ स्पेशल कमेटी.

28 जुलै से 3 अगस्त शहीद सप्ताह मनाओं!

जनता के लिए जान कुर्बान करने वाले वीर योध्दाओं को लाल सलाम!

जनता के मुक्ति के लिए जो वीर योध्दा जनयुध्द मे बलिदान देते है वे शहीद होते है। उनका लक्ष्य हर तरह के शोषण, जुल्म, दमन, लुट और अन्याय से जनता को मुक्ति दिलाने का होता है। जो जनसंग्राम मे वीरगति प्राप्त होता है वही शहीद कहलाता है। जीवनभर निस्वार्थ रुप से जनता के लिए संघर्ष करने वाले, अपना सर्वस्व जनता के खातिर अर्पण करने वाले शहीद होते है। इन वीर शहीदों की मृत्यू हिमालय से भी उँची होती है। वे मृत्यूंजयी होते है और सदैव जनता के दिलों मे रहते है। मानवी समाज के इतिहास मे ऐसे वीरों की कुर्बानीयों से ही नये सामाजिक मुल्यों की रचना हुई है और समाज विकसित होते हुए आगेकुच किया है। प्रकृति मे जीसका जनम हुआ उसका मृत्यू भी होना ही है, यह अटल है, यह प्रकृति का नियम है पर जीने–मरने मे जो सामाजिक मुल्य निर्माण कर इस दुनिया से विदाई लेता है वह अमर हो जाता है।

प्रकृति की अधभुत रचना मानव है, इन्ही मानव मे एक वो है जो प्रकृति के साथ सामाजिक विकास करते हुए आगे बढ़ते है तो दुसरे चंद ऐसे है जो अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति का विनाश कर रहे है। तमाम साम्राज्यवादी, सामंतवादी, दलाल नौकरशहा पूंजीपति, जमीनदार और इनके पक्ष मे खड़े वे तमाम राजनीतिज्ञ हो या बुध्दिजिवी हो जिनके पास सत्ता की कितनी भी ताकद क्यों न हो पर यह सबके सब अपने स्वार्थ के खातिर प्रकृति और समाज का विनाश कर रहे है। यह मुनाफेखोरी मे इतने अंधे हो गए है कि वे यह भी नही देख पा रहे है कि इस विनाश मे वे खुद भी नेस्तनाबुत होनेवाले है। दुनिया को कब्जे मे रखने वाले अमेरिका, रशिया, युरोप, जापान, चीन और उनकी चाटुकारीता मे खुदको धन्य समजनेवाले नरेन्द्र मोदी जैसे नेता समाज और प्रकृति के अपराधी है। हमारी लड़ाई इन्ही मुनाफेखोरो,(आगे पेज नंबर 42 पर)